मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 37 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 10 – 16 सितंबर 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला 3

अडाणी समूह के खिलाफ जांच क्यों नहीं कराती मोदी सरकार.............................5

इंडिया गठबंधन की मुंबई मीटिंग: एकता के लिए, विजय के लिए

जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया

डॉ. भालचंद्र कांगो

इंडिया गठबंधन (आईएनडीआईए– इंडियन नेशनल डवलपमेन्टल इनक्लूजिव अलायन्स यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) की तीसरी मीटिंग 31 अगस्त और 1 सितंबर 2023 को मुंबई में ग्रांड हयात होटल में हुई। पहली मीटिंग पटना में दूसरी मीटिंग बंगलुरू में हुई थी। मुंबई में आयोजित दो दिवसीय बैठक इंडिया के एजेंडे को कारगर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए और 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए चार महत्वपूर्ण समितियों को बनाने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ''जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया'' के नारे की सभी ने प्रशंसा की और यह गठबंधन का मुख्य नारा बन गया है। मीटिंग में नोट किया गया कि भारतीय जनता पार्टी 'फूट डालो और राज करो' के औपनिवेशिक जमाने के सांप्रदायिक एजेंडे को जारी रख रही है और संयोगत: विपक्ष के गठबंधन को राष्ट्रविरोधी बताने के भाजपा के एजेंडे की काट करने के लिए ''जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया'' का नारा एक कारगर नारा है। अत: भाजपा इंडिया गठबंधन की हर मीटिंग पर बौखलाई हुई है। अत: उसने रसोई गैस की कीमत को 200 रु. प्रति सिलेंडर घटा दिया और ''एक राष्ट्र, एक चुनाव '' के नारे के अंतर्गत संसद और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर अध्ययन करने और सिफारिश करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति की घोषणा की।

विपक्ष की सभी पार्टियों ने भाजपा के इस एजेंडे का विरोध किया है। यह स्पष्ट है कि महंगाई, बेरोजगारी, हरियाणा और मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव, जो भाजपा सरकार की अक्षमता एवं निकम्मेपन और भाजपा के डबल इंजन की सरकार के सिद्धांत की विफलता को दर्शाता है, जैसी ज्वलंत समस्यावों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है।

''एक राष्ट्र, एक चुनाव'' के नारे के जरिये सरकार भाजपा–आरएसएस के निरकुंशतापूर्ण, संघवाद विरोधी और सांप्रदायिक एजेंडे को और आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने आरोप लगाया कि सरकार अन्य राजनीतिक पार्टियों से सलाह–मशविरा किए बगैर एकतरफा फैसले कर रही है।

मीटिंग में विपक्ष के अधिकांश नेताओं ने अपनी बात कही और एकताबद्ध होकर संघर्ष करने का अपना संकल्प व्यक्त किया और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। एक अभियान समिति और मीडिया एवं सोशल मीडिया समिति के साथ–साथ एक समन्वय समिति भी बनाई गई। 1 सितंबर को मीटिंग समाप्त होने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को उद्धव ठाकरे, मल्लिकाअर्जुन खरगे, लालू प्रसाद, स्टालिन और राहुल गांधी समेत विभिन्न नेताओं ने संबोधित किया। मंच पर सभी पार्टियों के नेता उपस्थित थे।

मीटिंग का प्रारंभ चंद्रयान की सफलता पर इसरो, और हमारे तमाम वैज्ञानिकों एवं चंद्रयान–3 परियोजना की सफलता से जुड़े स्टाफ का अभिनंदन करते हुए एक निर्विरोध प्रस्ताव पारित किए जाने के साथ हुआ। तीन अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए। वे हैं:

■ आगामी लोकसभा चुनावों को यथासंभव मिलकर, एकजुट होकर लड़ना।

■ विभिन्न राज्यों में सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी और शीघ्र से शीघ्र इस काम का समापन किया जाएगा।

■ जनता के सरोकारों से जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में देश के विभिन्न हिस्सों में जल्द से जल्द

जन–रैलियां आयोजित करना।

■ कम्युनिकेशन और मीडिया रणनीतियों और ''जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया'' के नारे पर विभिन्न भाषाओं में अभियान को समन्वित करना।

इंडिया गठबंधन की मुंबई में आयोजित मीटिंग की सफलता शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ लेकर उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए शानदार समन्वयन और व्यवस्था से संभव हुई। 30 अगस्त को इंडिया गठबंधन के समर्थकों की एक बड़ी मीटिंग मुंबई में हुई जिसे डी. राजा, दीपंकर भट्टाचार्य, अशोक धावले, मेधा पाटेकर एवं अन्य ने संबोधित किया।

इंडिया गठबंधन की मुंबई में आयोजित इस मीटिंग में निम्न समितियां बनाने का फैसला भी किया गया:

समन्वयन और चुनाव रणनीति समिति

इसके सदस्य हैं: के.सी. वेणुगोपल (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस), शरद पवार (एनसीपी), टी.आर. बालू (डीएमके), हेमंत सोरेन (झारखंड मुक्ति मोर्चा), संजय रावत (शिवसेना), तेजस्वी यादव (राजद), अभिषेक बैनर्जी (तृणमूल कांग्रेस), राघव चड्ढ़ा (आम आदमी पार्टी), जावेद अली खान (सपा), लल्लन सिंह (जदयू), डी.राजा (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी), उमर अब्दुल्ला (नेशनल कॉन्फ्रेंस), महबूबा मुफ्ती (पीडीपी) और एक सदस्य भाकपा (मा) के (जिनका नाम बाद में पार्टी देगी)।

अभियान समिति

इसके सदस्य हैं: गुरदीप सप्पल (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस), संजय झा (जदयू), अनिल देसाई (शिवसेना), संजय यादव (राजद), पी.सी. चाको (एनसीपी), चम्पई सोरेन (झारखंड मुक्ति मोर्चा), किरणमय नंदा (सपा), संजय सिंह (आम आदमी पार्टी), अरूण कुमार भाकपा (मा), बिनोय विश्वम (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी), जस्टिस (रि.) हसनैन मसूदी (नेशनल कॉन्फ्रेंस), शाहिद सिद्दिकी (राष्ट्रीय लोक दल), एन.के. प्रेमचन्द्रन (आरएसपी), जी देवराजन (ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक), रवि राय (भाकपा(एमएल)), तिरुमावलन (वीसीके), के.एम.कादर मोइद्दीन (इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग), जोसे के. मणि (केरल कांग्रेस (एम)) और एक सदस्य तृणमूल कांग्रेस के (जिनका नाम बाद में पार्टी देगी)।

सोशल मीडिया के लिए वर्किंग ग्रुप

इसके सदस्य हैं: सुपिया श्रीनेते (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस), सुमित शर्मा (राजद), आशीष यादव (सपा), राजीव निगम (सपा), राघव चड्ढ़ा (आम आदमी पार्टी), अविन्दानी (झारखंड मुक्ति मोर्चा), इल्तिजा महबूबा (पीडीपी), प्रांजल (भाकपा (मा)), डॉ. भालचंद्र कांगो (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी), इफरा जान (नेशनल कॉन्फ्रेंस), बी. अरूण कुमार (भाकपा (एमएल)), और एक सदस्य तृणमूल कांग्रेस के (जिनका नाम बाद में पार्टी देगी)।

मीडिया के लिए वर्किंग ग्रुप

इसके सदस्य हैं: जयराम रमेश (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस), मनोज झा (राजद), अरविन्द सावन्त (शिवसेना), जितेन्द्र अहवाड (एनसीपी), राघव चड्ढ़ा (आम आदमी पार्टी), राजीव रंजन (जदयू), प्रांजल (भाकपा(मा)), आशीष यादव (सपा), सुप्रिय भट्टाचार्य (झारखंड मुक्ति मोर्चा), आलोक कुमार (झारखंड मुक्ति मोर्चा), मनीष कुमार (जदयू), राजीव निगम (सपा), डॉ. भालचंद्र कांगो (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी), तनवीर सादिक (नेशनल कॉन्फ्रेंस), प्रशांत कनौजिया (सपा), नरेश चटर्जी (ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक), सुचेता डे (भाकपा(एमएल)), मोहित भान (पीडीपी), और एक सदस्य तृणमूल कांग्रेस के (जिनका नाम बाद में पार्टी देगी)।

अनुसंधान के लिए वर्किंग ग्रुप

इसके सदस्य हैं: अमिताभ दुबे (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस), प्रो. सुबोध मेहता (राजद), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना), वन्दना चवाण (एनसीपी), के.सी. त्यागी (जदयू), सुदिव्य कुमार सोनू (झारखंड मुक्ति मोर्चा), जेस्मिन शाह (आम आदमी पार्टी), आलोक रंजन (सपा), इमरान रबी डार (नेशनल कॉन्फ्रेंस), एडवोकेट आदित्य (पीडीपी) और एक सदस्य तृणमूल कांग्रेस के (जिनका नाम बाद में पार्टी देगी)।

संपादकीय

कॉरपोरेट सेक्टर का ऐतिहासिक घोटाला

एक बार फिर से अदानी ग्रुप पर चार्ज लगने शुरू हो गए हैं। 2022 में भी उन पर आरोप लगे थे, जब खोजी पत्रकारों के ग्रुप ने, जो विश्व स्तर पर सक्रिय रहता है, उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लाखों की रकम अपने तट से दूर की कंपनियों के ढांचे, उनकी संरचनाओं पर खर्च किया था।

अदानी ग्रुप ने संगठित अपराध और भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग की परियोजना (ओसीसीआरपी) में लगे अपने ऊपर आरोपों को हिंडेनबर्ग की दिशाहीन रिपोर्ट में लगे भ्रामक आरोपों के ग्रुप में देखा है। अदानी ग्रुप ने उसे सिरे से अस्वीकार किया है और कहा है कि यह सोरोस फंड की एक और कोशिश है और इसमें विदेशी मीडिया का एक हिस्सा भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फिर से जिन्दा करने की कोशिश कर रहा है।

इस बार ओसीसीआरपी की खोजी पत्रकारिता से निकले रिपोर्ट की बुनियाद पर गार्डियन और फाइनेन्शियल टाइम्स में भी लिखा गया है और इसके चलते अदानी ग्रुप के दस स्टॉक्स की बाजार दर अब गिरकर मात्र 35,210 करोड़ रह गई है। गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी के एसोसिएट और किसी प्रोमोटर ग्रुप से जुड़े होने का, साथ ही बरमुडा के एकविदेशी फंड से जुड़े जटिल संरचनाओं के जाल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के साथ व्यापार करने के लिये बुने गऐ थे यह आरोप भी है। यूनाइटेड अरब एमिदार से अली शाबान अहली और चांग चुंग लिंग ताइवान से आने वाले दो व्यक्ति थे जिनका जुड़ाव अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के साथ था और उनका ग्लोबल ऑपरचुनिटीज फंड का व्यापार होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी अदानी ग्रुप के साथ अपने संबंधों पर प्रकाश नहीं डाला। यह सब 2010 से ही चला रहा है। बात यहीं तक नहीं है। रिपोर्ट्स इस पर भी आ रहे हैं कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेन्स (डीआरआई), ने जो भारत की तस्करी विरोधी सूचनाओं को एकत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था है और वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती हे, अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बाजार को संतुलित करने वाली सिक्यूरिटिज और एक्सचेंज बोर्ड के (सेबी) रूप में काम करने वाली यह संस्था जो सेबी कहलाती है और 2014 में ही अपतटीय (ऑफ शोर) सक्रियता के बारे में सावधान कर चुकी है। सेबी ने सर्वोच्च न्यायालय से यह भी कहा है कि 2020 से ही अदानी ग्रुप पर उसकी नजर है। लेकिन यह संदेह रह ही जाता है कि इस रेगुलेटर ने डीआरआई द्वारा दिये गये सूत्रों पर कोई खोज शुरू भी की या नहीं साथ ही पहले की गई जांच पड़ताल से कोई सुराग मिला या नहीं और इसकी बुनियाद पर जांच आगे बढ़ी या नहीं।

सेबी के पूर्व अफसर ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि सेबी हर शिकायत पर पूरा ध्यान देती है, और नियमानुसार ही अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। उन्होंने कहा कि ''उस समय हमने अदानी ग्रुप की अनियमितता पर पड़ताल शुरू की थी या नहीं, मैं यह नहीं बता सकता क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है। सब जूडिस, लेकिन इतना जरूर ध्यान में रहना चाहिये कि ऐसी किसी भी जांच के लिये हमें विदेशी सहायता की जरूरत अनिवार्य रूप से पड़ती है और यह भी सही है कि सभी विदेशी सहायता उपलब्ध नहीं भी होती है।'' बिना कोई विस्तृत सूचना दिये, उस अधिकारी ने यहां तक ही बताया।

सूत्रों के अनुसार यू.के. सिन्हा 2014 में सेबी के चेयरमैन थे। इस साल की शुरूआत में उन्हें न्यू दिल्ली टेलिविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) की दिल्ली शाखा का अध्यक्ष बना दिया गया। इस दिशा में इससे अधिक जान पाना कठिन ही हो गया।

अदानी ग्रुप ने अपने पक्ष में यह भी कहा कि ओसीसी आरपी और डीआरआई में जो मुकदमे दायर किए गए थे, उसके तो एक दशक तक का समय हो गया और कुछ भी नहीं निकला। यहां तक कि अदानी ग्रुप को सर्वोच्च न्यायालय से भी क्लीन चिट मिल गया था। इसमें फंड का विदेशों में भेजना, इससे जुड़े अन्य संबद्ध पार्टी से किसी तरह का लेन–देन, और निवेश, जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो का भी दाम लगा हो, इस तरह के आरोप भी थे। ''एक स्वतंत्र निर्णायक शक्ति का अधिकारी और एक एपीलेट ट्रिब्यूनल, दोनों ने ही मिलकर आरोपों का खंडन किया और कहा कि सारी लेन–देन कानूनी तौर पर हुई है।'' अदानी ग्रुप ने अपने बचाव में कहा। सेवी के अनुसार सबसे कम पब्लिक शेयर होल्डिंग के तरीके प्रोमोटर्स को किसी कंपनी में 75 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा लेने से रोका जाता है। अगर कोई फंड प्रोमोटर्स से मिलकर लगाया जाता है तो फंड में जितने शेयर हैं, वे प्रोमोटर्स ग्रुप के लिये भी होंगे। इसलिये उन आरोपों का महत्व बढ़ जाता है। अदानी ग्रुप की ताकत और ख्याति तथा प्रभाव 2014 से ही बढ़ना शुरू हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र में बंदरगाहों, विद्युत केन्द्रों, कोयलों की खदानों, हाइवे, एनर्जी पार्क, हवाई अड्डा और झुग्गी–झोपड़ियों के इलाके का विकास का कांट्रेक्ट्स भी आसानी से मिलने लगा। इस तरह अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की वैल्यू भी बढ़कर 2013 में जो आड बिलियन डॉलर था, वह 288 बिलियन डॉलर सितंबर, 2022 में हो गया।

न्यूयार्क फाईनेन्शियल रिसर्च फर्म हिन्डेनबर्ग ने जनवरी की अपनी एक रिपोर्ट में कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े घोटाले के रूप में अदानी ग्रुप के घोटाले को रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी रखी है जो फरवरी में फाइल की गई एक रिट पिटीशन को संज्ञान में रखते हुए अदानी–हिंडनबर्ग कथा की हर परत को जांच में लेगी। इसकी अदानी ग्रुप पर की गई जांच पर निर्भर करते हुए सेबी ने कहा कि वह मीनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की जांच अभी पूरा नहीं कर पाई है क्योंकि सेबी को अभी तक विदेशी रेगुलेटर्स की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है।

इस बीच श्री मोदी जी से जुड़े अदानी परिवार ने लाखों डालर भारत के शेयर मार्केट में लगाए और अपने शेयर भी खरीदे। विदेशी वित्त संबंधी भी रिकॉर्ड्स के अनुसार अदानी परिवार से जुड़े परिवार के सदसयों ने अदानी ग्रुप की अपनी कंपनियों, जो विकास में आसमान छू रहा था, भारत की सबसे धनी और सशक्त व्यापार की स्वामिनी बन चुकी थी, उनसे स्टॉक लिये, जो चुपचाप सालों से चल रहा था, दुनिया की नजरों से दूर/2022 तक गौतम अदानी भारत का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका ाि और विश्व के धनी व्यक्तियों में तीसरा स्थान 2022 तक पा चुका था क्योंकि अब उसकी संपत्ति 120 बिलियन पाउन्ड तक पहुंच चुकी थी।

भाजपा हटाओ देश बचाओ, नया भारत बनाओ रैली की तैयारी

दो नवम्बर रैली की तैयारी में लगी बिहार भाकपा

मधुबनीः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला परिषद की बैठक दो सितम्बर को मो. जहागीर की अध्यक्षता में पार्टी जिला कार्यालय के भोगेंद्र झा सभागार में हुई। बैठक में जिला मंत्री मिथिलेश झा द्वारा विगत दो महीने की पार्टी की सांगठनिक एवं आंदोलनात्मक गतिविधियों के बारे में कार्य रिपोर्ट पेश की गयी। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी राज्य सचिव एवं पूर्व विधायक रामनरेश पांडेय ने कहा देश में अशांति एवं आक्रोश का माहौल व्याप्त है। बेरोजगारी तथा महंगाई से आमलोग परेशान हैं। नौजवानों को रोजगार के तलाश में भटकना पर रहा है। केंद्र सरकार मीडिया के सहारे अपना प्रचार प्रसार करने में व्यस्त है। रामनरेश पांडेय ने कहा कि जब तक बिहार में बीजेपी सरकार का हिस्सा थी तब रोजगार के सवाल पर चुप थी, परंतु आज जब उन्हें सत्ता से हटना पड़ा है तब बिहार में सब कुछ ठीक नही लग रहा है। उन्होंने कहा आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में तीन सीट मधुबनी, बेगूसराय एवं बांका को पहली प्राथमिकता की सूची में चयनित किया गया है। केंद्र में सत्तारूढ़ पूंजीवादी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए भाकपा, 2 नवंबर 2023 को पटना क गांधी मैदान में अपनी शक्ति दिखायेगी। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, के नारा के साथ 2 नवंबर की रैली में 3 लाख पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक पटना के गांधी मैदान में उतरेंगे। भाकपा के राज्य सचिव नेतृत्व में शिक्षकों के सवालों को लेकर अपनी ही महागठबंधन के सरकार पर दबाव बनाते हुए महागठबंधन के नेता से वार्ता के लिए सरकार को मजबूर किया गया।

रामनरेश पांडेय ने कहा कि ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के सवाल पर राज्य के मुखिया महासंघ के मांगों को लेकर हमारी पार्टी सरकार से वार्ता करेगी। पंचायतों को सशक्त बनाने के हरेक आंदोलन को भाकपा का समर्थन रहेगा।

दरभंगा

2 नवंबर को सीपीआई की 'भाजपा हटाओ देश बचाओ' महारैली पटना के गांधी मैदान में होगी जिसकी तैयारियों को लेकर बिहार भाकपा कली जिलावार तैयारी मीटिंगें चल रही हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दरभंगा की जिला परिषद् की बैठक जिला कार्यालय लालबाग में राम श्रृंगार सिंह की अध्यक्षता में हुई। जिसमें सर्वसम्मति से 2 नवंबर को पटना के गाँधी मैदान में अखिल भारतीय खेत–मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर पटना के गाँधी मैदान में 'भाजपा भगाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ महारैली' का आयोजन किया जायेगा। जिसमें दरभंगा से हजारों हजारों की संख्या में लोगों को गोलबंद कर ले जाने का फैसला हुआ। वहीं 11, 12 और 13 सितंबर को प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर जनता के ज्वलंत मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन की योजना बनी। सितंबर माह के अंत तक सभी शाखा, अक्टूबर के अंत तक अंचल सम्मेलन हर हाल में करने की सहमति बनी। वहीं शाखा सम्मेलन की तैयारी के क्रम में प्रत्येक सदस्य व समर्थक से पार्टी कोष के लिए सहयोग शुल्क लेने पर सहमति बनी। 20 सितंबर को दरभंगा जिला किसान सभा की सिंघवारा में आयोजित होने वाले जिला सम्मेलन में जिला के कोने–कोने से किसानों को गोल बंद कर भेजने की बात हुई। वहीं 28 सितंबर को बेगूसराय में आयोजित ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में पूरे जिले भर से हजारों हजार की संख्या में छात्रों को जोड़कर वहां आयोजित 'शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, रोजगार बचाओ' महारैली को सफल बनाने पर सहमति बनी। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव विधायक रामनरेश पांडे ने कहा कि देश के अंदर फासीवादी सरकार लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ाकर यहां के लोगों का जीना दूभर कर दिया है। वहीं अब सरकार के खिलाफ जनता गोलबंद हो गई है। जनता की मांगों पर सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडिया नामक गठबंधन का निर्माण किया है। इंडिया के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजबूती के साथ है। पार्टी जन आंदोलन से लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ रहेगी। वहीं उन्होंने शिक्षकों के आंदोलन में सरकार द्वारा बेहतर पहल कर आंदोलन को समाप्त करवाने पर सरकार की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षकों की मांग जायज है और इस पर सरकार गंभीरता से शिक्षक के हितों में फैसला करें। वही बिहार के अंदर चल रहे मुखियाओं के आंदोलन का भी पार्टी समर्थन करती है। वहीं अविलंब सरकार मुखिया महासंघ के नेताओं से वार्ता कर उनके मांगों को हर–हाल में पूरी करने की हम अपील करते हैं।

अडानी पर ओसीसीआरपी की ताजा रिपोर्ट

भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला

हिन्डनबर्ग के बाद अब ओसीसीआरपी (ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एण्ड क्रप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट) की अडानी पर ताजा रिपोर्ट ने ना केवल अडानी समूह को हिलाकर रख दिया है बल्कि मोदी सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं।

ओसीसीआरपी द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट एवं दस्तावेज स्टॉक में हेरफेर की ताजा जानकारी देते हैं। साथ रिपोर्ट उन दो विदेशी लोगों को भी सामने लाती है जिन्होंने भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर अडानी की कंपनी में निवेश किया और जिनके अडानी परिवार से घनिष्ठ संबंध बताये जाते हैं।

अमेरिकी शार्ट सेलिंग कंपनियों के नियोक्ताओं ने अपने ताजा आरोपों में अडानी कंपनी करे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हालांकि अडानी के इन सभी लेनदेन का विदेशी गोपनीयता कानूनों के कारण पता लगा पाना मुश्किल है। वैसे इस रिपोर्ट का मानना है कि अडानी की कंपनी के कुछ निवेशक मालिक वास्तव में मुखौटा भर हैं।

रिपोर्ट में दिये गये दस्तावेजों से पता चलता है कि दो लोगों ने अडानी समूह में करोडों रूपये का कारोबार किया। इन दो लोगों के नाम हैं नासिर अली शाबान और चुंग लिंग। अडानी समूह के इन दोनों निवेशकों का अडानी परिवार से करीबी संबंध बताया जाता है। रिकॉर्डो से मालूम हुआ कि जिस निवेश फण्ड का निवेश के लिए उपयोग किया गया वह अडानी परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा नियंत्रित और निर्देशित बतायी जाता है। इस रिपोर्ट में हवाई अड्डों से लेकर मीडिया कंपनियों तक में रूचि रखने वाली कंपनी भारतीय इतिहास की सबसे बड़े आर्थिक घोटालों के लिए बदनाम कंपनी बनती जा रही है। यहां तक कि अमेरिका के न्यूयार्क की शार्ट सेलिंग कंपनी के आरोपों के कारण कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना और यहां तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को इन आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी गठित करनी पड़ी।

जनवरी में एक शार्ट सेलर कंपनी द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच बेशक सुप्रीम कोर्ट ने करने के आदेश दिये परंतु यह जांच विदेशी गोपनीयता कानूनों के कारण उन निवेशकों की पहचान कर पाने में सक्षम नहीं हो पायी जिन पर आरोप था कि वे वास्तव में अडानी के ही करीबी थे। ऐसा नहीं हो पाने का कारण अडानी की मोदी से करीबी को कारण माना जा रहा है।

अब ओसीसीआरपी द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट जिसमें दा गार्जियन और फाइनैंशियल टाइम्स के साथ साझा किए गए विशेष दस्तावेजों का हवाला दिया गया है वे कई टैक्स हेवन्स, अडानी कंपनी के अंदरूनी ईमेल्स के माध्यम से इस पूरे मामले पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं।

ये दस्तावेज, जिन्हें कई देशों के अडानी समूह के व्यवसाय और सार्वजनिक रिकॉर्ड की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले लोगों द्वारा पुष्टि की गई है, दिखाते हैं कि कैसे मॉरीशस में स्थित अपारदर्शी निवेश कोष के माध्यम से सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले अदानी स्टॉक में करोड़ों डॉलर का निवेश किया गया था। कम से कम दो मामलों में – अडानी स्टॉक होल्डिंग्स का प्रतिनिधित्व करते हुए, जो निवेश एक समय में 430 मिलियन डालर तक पहुंच गया था – रहस्यमय निवेशकों का संबंध समूह के शेयरधारकों, अडानी परिवार के साथ व्यापक रूप से संबंध होने का इशारा किया है।

दो व्यक्तियों, नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग–लिंग के अडानी परिवार के साथ लंबे समय से व्यापारिक संबंध हैं और उन्होंने अडानी समूह की कंपनियों और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों में से एक विनोद अडानी से जुड़ी कंपनियों में निदेशक और शेयरधारक के रूप में भी काम किया है।

दस्तावेजों से पता चलता है कि, मॉरीशस फंड के माध्यम से, उन्होंने वर्षों तक ऑफशोर संरचनाओं के माध्यम से अडानी स्टॉक खरीदे और बेचे और उससे मुनाफा कमाया है। वे यह भी दिखाते हैं कि उनके निवेश की प्रबंधन कंपनी ने विनोद अडानी कंपनी को उनके निवेश पर सलाह देने के लिए भुगतान किया था।

यह व्यवस्था कानून का उल्लंघन है या नहीं, इसका सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अहली और चांग को अडानी 'प्रमोटरों' की ओर से काम करने वाला माना जाना चाहिए। यदि ऐसा है, तो अदानी समूह में उनकी हिस्सेदारी का मतलब यह होगा कि अंदरूनी सूत्रों के पास कुल मिलाकर कानून द्वारा अनुमत 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि जब कंपनी 75 प्रतिशत से ऊपर अपने शेयर खरीदती है... तो यह न केवल अवैध है, बल्कि यह शेयर की कीमत में हेरफेर भी है। इस तरह कंपनी कृत्रिम कमी पैदा करती है, और इस प्रकार अपने शेयर मूल्य को बढ़ाती है–और इस प्रकार इसका अपना बाजार पूंजीकरण होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उन्हें यह छवि हासिल करने में मदद मिलती है कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें कर्ज प्राप्त करने, कंपनियों के मूल्यांकन को नई ऊंचाई पर ले जाने और फिर नई कंपनियां बनाने में मदद मिलती है। यह सारा खेल जो सालों से एक समय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी के अडानी समूह द्वारा खेला जा रहा है।

रिपोर्ट छापने के समय इस स्टोरी पर कमेंट के लिए अडानी समूह से आग्रह पर अडानी समूह के एक प्रतिनिधि ने कहा कि पत्रकारों द्वारा जांच की गई मॉरीशस फंड का नाम पहले से ही 'हिंडनबर्ग रिपोर्ट' में शामिल था। (रिपोर्ट में इन ऑफशोर कंपनियों का नाम बताया गया है, लेकिन यह खुलासा नहीं किया गया है कि अदानी स्टॉक में निवेश करने के लिए उनका उपयोग कौन कर रहा था।) अडानी समूह के प्रतिनिधि ने सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति का भी हवाला दिया, जिसने मामले की तह तक जाने के वित्तीय नियामक के प्रयासों को 'साबित नहीं होना' बताया। प्रतिनिधि ने लिखा कि इन तथ्यों के आलोक में, ये आरोप न केवल निराधार बल्कि हिंडनबर्ग के आरोपों को दोहराया गया है। आगे, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अडानी समूह की सभी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध संस्थाएं सार्वजनिक शेयर होल्डिंग्स से संबंधित विनियमन सहित सभी लागू कानूनों का अनुपालन करती हैं। अहली और चांग ने टिप्पणी के लिए ओसीसीआरपी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। द गार्जियन के एक रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में, चांग ने कहा कि उन्हें अडानी स्टॉक की किसी भी गुप्त खरीद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या उन्होंने कोई खरीदारी की है, लेकिन पूछा कि पत्रकारों को उनके अन्य निवेशों में दिलचस्पी क्यों नहीं है। साक्षात्कार समाप्त करने से पहले उन्होंने कहा कि हम एक साधारण व्यवसायी हैं।

विनोद अडानी ने टिप्पणी के लिए किये गये अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। हालाँकि अडानी समूह ने इस बात से इनकार किया है कि समूह को चलाने में उनकी कोई भूमिका है, लेकिन इस मार्च में उन्होंने स्वीकार किया था कि वह इनके 'प्रमोटर समूह' का हिस्सा थे–जिसका अर्थ है कि कंपनी के मामलों पर उनका नियंत्रण था और उन्हें सभी होल्डिंग्स के बारे में सूचित किया जाना था। अडानी समूह के एक प्रतिनिधि ने संवाददाताओं से कहा कि विनोद अडानी की संलिप्तता का 'विधिवत खुलासा' किया गया है, और कहा कि वह एक 'विदेशी नागरिक हैं... पिछले तीन दशकों से विदेश में रह रहे हैं' और 'किसी भी अडानी सूचीबद्ध संस्था या उनकी कंपनी में कोई प्रबंधकीय पद पर नहीं हैं।

'बेशर्म स्टॉक हेराफेरी'

अडानी समूह की वृद्धि आश्चर्यजनक रही है, मोदी के प्रधानमंत्री बनने से एक साल पहले सितंबर 2013 में बाजार पूंजीकरण 8 अरब डॉलर से बढ़कर पिछले साल उनका पूंजीकरण 260 अरब डॉलर पहुच गया है। यह समूह परिवहन और रसद, प्राकृतिक गैस वितरण, कोयला व्यापार और उत्पादन, बिजली उत्पादन और वितरण, सड़क निर्माण, डेटा केंद्र और रियल एस्टेट सहित कई क्षेत्रों में सक्रिय है। इसने राज्य के कई सबसे बड़े टेंडर भी हासिल किय हैं, जिनमें भारत के कई हवाई अड्डों के संचालन या पुनर्विकास के 50–वर्षीय अनुबंध भी शामिल हैं। हाल ही में, इसने देश के आखिरी स्वतंत्र टेलीविजनों में एक एनडीटीवी पर भी निर्णायक हिस्सेदारी हासिल कर ली है।

लेकिन अडानी का उदय बिना विवादों से परे नहीं रहा। विपक्षी राजनेताओं का आरोप है कि कंपनी को अपने स्टेट टेंडर हासिल करने में राज्य की प्राथमिकता हासिल रही है। विश्लेषकों का कहना है कि इसके मुखिया गौतम अडानी को मोदी के साथ घनिष्ठ संबंधों का लाभ मिल रहा है। अडानी ने इस बात से इनकार किया है कि उनके व्यापारिक साम्राज्य की सफलता के लिए मोदी या उनकी नीतियां जिम्मेदार हैं।

हालांकि इस समूह को जनवरी के अंत में एक बड़ा झटका लगा तब लगा जब न्यूयॉर्क स्थित शार्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि समूह ने दशकों तक 'बेशर्म स्टॉक हेरफेरी' और 'लेखा धोखाधड़ी' की है। इस खबर की हेडलाइन में लिखा था, गौतम अडानी 'कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहे थे।' रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मुख्य मुद्दा यह था कि कंपनी भारतीय प्रतिभूति कानून का उल्लंघन कर रही थी। रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद, समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। गौतम अडानी को कुछ ही दिनों में 60 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ और वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी से गिरकर 24वें स्थान पर आ गए।

जवाब में, अडानी समूह ने खंडन जारी किया और खुद को भारतीय तिरंगे की आड के पीछे लेने की कोशिश की। और समूह ने राष्ट्रवादी कार्ड खेलते हुए सभी हितधारकों को एक नोट में लिखा कि यह केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अनुचित हमला नहीं है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता, अखंडता और भारतीय संस्थानों की गुणवत्ता, और भारत की विकास कहानी और महत्वाकांक्षा पर एक सोचा–समझा हमला है।

इस बीच, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जवाब में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बुलाई। इस मई में प्रकाशित समिति के निष्कर्षो से पता चला कि अडानी समूह की भारतीय वित्तीय नियामक सेबी द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है। समिति के अनुसार, सेबी को वर्षों से संदेह था कि 'अडानी समूह के, कुछ सार्वजनिक शेयरधारक वास्तव में सार्वजनिक शेयरधारक नहीं हैं और वे 'अडानी समूह, प्रमोटरों के मुखौटे हो सकते हैं।' 2020 में, इसने अडानी स्टॉक रखने वाली 13 विदेशी संस्थाओं की जांच शुरू की। लेकिन विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि सेबी जांचकर्ता निर्णायक रूप से यह निर्धारित नहीं कर सके कि पैसे के पीछे कौन था। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा करने का प्रयास 'बिना डेस्टिनेशन की यात्रा' होगी, क्योंकि स्टॉक के अंतिम मालिकों को छिपाने के लिए अपारदर्शी कॉर्पोरेट स्वामित्व की कई परतों का उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, पत्रकारों द्वारा प्राप्त दस्तावेज 13 अपतटीय संस्थाओं में से दो से जुड़े दो मामलों में 'डेस्टिनेशन्स' का खुलासा करते हैं: जो मॉरीशस–आधारित निवेश फण्ड की एक जोड़ी है।

बाहर से देखने पर ये फंड, जिन्हें इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड (ईआईएफएफ) और ईएम रिसर्जेंट फंड (ईएमआरएफ) कहा जाता है, विशिष्ट ऑफशोर निवेश माध्यम प्रतीत होते हैं, जो कई धनी निवेशकों की ओर से संचालित होते हैं। ओसीसीआरपी के पत्रकारों द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि पैसे का एक बड़ा हिस्सा दो विदेशी निवेशकों–ताइवान के चांग और संयुक्त अरब अमीरात के अहली–द्वारा इन फंडों में लगाया गया था, जिन्होंने 2013 और 2018 के बीच चार अडानी कंपनियों में बड़ी

शेष पेज 10 पर...

कुछ सामयिक मुद्दे और घटनाक्रम

आर.एस. यादव

एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर

पिछले दिनों 7 से10 अगस्त के बीच एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के तीन पत्रकारों–सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर की तथ्यान्वेषी टीम ने हिंसाग्रस्त मणिपुर राज्य का दौरा किया। टीम ने ...अगस्त को अपनी रिपोर्ट जारी की।

इस रिपोर्ट के जारी होते ही मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने एक पत्रकार सम्मेलन बुलाकर कहा कि उनकी सरकार ने एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और तथ्यान्वेषी टीम के तीनों पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उन पर राज्य में दंगे भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''वे राज्य विरोधी, राष्ट्रविरोधी और सत्ताविरोधी हैं जो जहर उगलने आए थे। पहले से पता होता तो घुसने नहीं देता। ....

एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि झगड़े के दौरान राज्य का नेतृत्व पक्षपातपूर्ण हो गया।.. ...राज्य सरकार को जातीय संघर्ष में पक्ष लेने से बचना चाहिए था, लेकिन यह एक लोकतांत्रिक सरकार, जिसे पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पड़ोसी म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट से भाग कर लगभग चार हजार शरणार्थियों के मणिपुर में प्रवेश करने के बाद मणिपुर सरकार ने सभी कुकी जनजातियों को ''अवैध अप्रवासी'' करार कर दिया। रिपोर्ट में ईजीआई ने राज्य सरकार को कई ऐसे कदम उठाने के लिए दोषी ठहराया जिनके कारण चिन–कुकियों में नाराजगी पैदा हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने कई पक्षपातपूर्ण बयानों और नीतिगत उपायों के माध्यम से कुकी के खिलाफ बहुमत के गुस्से को बढ़ावा दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मणिपुर में पत्रकारों पर, जाहिर है मैतई हों या आदिवासी, अपने जातीय समाज के प्रमुख दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के लिए अत्यधिक दबाव है और इंटरनेट पर प्रतिबंध के साथ स्थिति को और भी अधिक कठिन बना दिया गया है, जो आधुनिक पत्रकारिता का एक आवश्यक उपकरण है।......मीडिया में जातीय विभाजन इतना गहरा था कि समाचार कहानियों के साथ–साथ संपादकीय में कुकी आदिवासियों की रक्षा के लिए असम राइफल्स को दोषी ठहराया जाना लगा। कुकी–जोमी लोगों को ''नारको –आतंकवादी'' के रूप में वर्णित किया गया है जो ड्रग मनी का उदारतापूर्वक उपयोग करके भूमि से बंधे मणिपुर में अपना स्थान बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ''जातीय हिंसा के दौरान मणिपुर के पत्रकारों ने एकतरफा रिपोर्टें लिखीं। सामान्य परिस्थितियों में, उसके संपादकों या स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों के ब्यूरो के प्रमुख द्वारा उनकी क्रॉस चैकिंग और निगरानी हो सकती है, परंतु संघर्ष के दौरान यह संभव नहीं था.......मैतई मीडिया सुरक्षा बलों, विशेषकर असम राइफल्स की निंदा में एक पक्ष बन गया।''

एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और मुख्यमंत्री द्वारा गिल्ड के खिलाफ कटुतापूर्ण टिप्पणियां प्रेस की स्वतंत्रता के लिए घातक हैं। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसे सारा देश देख रहा है। सारी दुनिया देख रही है। राज्य में 3 मई से जारी हिंसा लगातार जारी है। अभी हाल में , 31 अगस्त को राज्य के कुकी–जोमी बहुल चुराचांदपुर और मैतई बहुल विष्णुपुर के बीच कुछ इलाकों में हुई हिंसा में 6 लोग मारे गए।

मणिपुर में हिंसा भड़कने के चार महीनों के अंदर मैतई बहुल इम्फाल में कुकी–जोमी समुदाय के हजारों लोग शहर छोड़ चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार, कुकी–जोमी समुदाय के 24 लोगों का एक समूह इम्फाल के एक इलाके में रूका हुआ था। उन्होंने अपने मोहल्लों को गेट लगाकर घेराबंदी कर रखी थी, इस इलाके में घुसने के सभी रास्तों को बंद कर रखा था, सभी रास्तों पर लकड़ी लगाकर किलेबंदी की तरह लकड़ी के सिरों को नुकीला कर रखा था। हिंसा फैलने के बाद वहां से 300 कुकी–जोमी पहले ही जा चुके थे। 3 सितंबर की आधी रात सुरक्षाकर्मियों ने इन लोगों को जबरन वहां से हटा दिया और उन्हें वाहन में भरकर कुकी बहुल इलाके में ले गए। सुरक्षा बलों के सूत्रों के अनुसार प्रशासन द्वारा उन्हें वहां से चले जाने का अनुरोध किया था क्योंकि कम तादाद होने के कारण वे लोग आसानी से निशाना बन रहे थे। व्यवहारिक तौर पर इन कुकी परिवारों को वहां से निकाल देने के बाद इम्फाल घाटी में जातीय सफाया पूरा हो गया है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री को इस तरह हो रहे जातीय सफाये के संबंध में चिंता होनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा मणिपुर के संबंध में चिंता

किस–किस के खिलाफ एफआईआर करेंगे मणिपुर के मुख्यमंत्री? 4 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भी मणिपुर में लगातार जारी हिंसा पर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाकर लिंग आधारित हिंसा की खबरें और तस्वीरें काफी चिंताजनक हैं। उन्होंने मणिपुर में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की खबरों को लेकर चिंता जताई है जिनमें यौन हिंसा, न्यायेतर हत्याएं, जबरन विस्थापन, यातना और दुर्व्यवहार के कृत्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और दमन को वैध बनाने के लिए आतंकवाद–रोधी कदमों के कथित दुरूपयोग से हम और चिंतित हैं।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने दावा किया कि मणिपुर की हाल की घटनाएं भारत में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की लगातार बिगड़ती स्थिति की दिशा में एक और दुखद मील का पत्थर है।

उन्होंने भारत सरकार से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयासों में तेजी लाने और हिंसा की जांच करने के लिए समय पर कार्यवाही करने और अधिकारियों से अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने का आग्रह किया। उन्होंने मणिपुर में वकीलों और मानवाधिकार रखकों द्वारा चलाए गए तथ्यान्वेषी मिशन और मणिपुर की स्थिति पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई का स्वागत किया, हालांकि प्रतिक्रिया समयबद्ध तरीके से की जा सकती थी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से न्याय, जवाबदेही और क्षतिपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार और अन्य संबंधित लोगों की प्रतिक्रिया की निगरानी जारी रखने का आग्रह किया।

मोदी सरकार के कुछ नए शगूफे

अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है कि ''इंडिया'' गठबंधन के रूप में विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से मोदी सरकार विचलित है। कई नए शगूफे छोड़ दिए गए हैं जैसे कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का नारा फिर से लगा दिया है, 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की गई है और कोई नहीं जानता उसका एजेंडा क्या है? रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपए की कमी की घोषणा कर दी गई है। नहीं मालूम अगले दिनों में अन्य कितनी अप्रत्याशित बातें सामने आ सकती हैं?

सरकार इस तरह की जल्दबाजी में है कि उसने ''एक राष्ट्र, एक चुनाव'' की संभावनाएं तलाश करने के लिए एक समिति का ही गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। समिति में कांग्रेस के भी एक नेता को शामिल किया गया परंतु कांग्रेस ने ऐसी समिति में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया।

भले ही सरकार ने कहा हो कि समिति ''एक राष्ट्र, एक चुनाव'' की संभावना तलाश करने के लिए बनाई गई है, परंतु सब जानते हैं कि समिति का बनाया जाना एक नाटक के अलावा कुछ नहीं। समिति को क्या रिपोर्ट देनी है, सरकार इसका फैसला पहले ही ले चुकी है, समिति को तो सिर्फ उस पर मुहर लगानी है।

संसद का विशेष सत्र बिना किसी एजेंडे के बुलाया जा रहा है। अतः स्वाभाविक है कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सरकार का इसके पीछे इरादा क्या है? इन अनुमानों में लोकसभा को भंग कर समय से पहले चुनाव कराने से लेकर समान नागरिक संहिता लागू करने जैसी बातें शामिल हैं। निश्चित तौर पर सरकार कोई न कोई ऐसे अप्रत्याशित कदम उठाने की दिशा में काम कर रही है जिन्हें वह लोकसभा के आगामी चुनाव और आगामी महीनों में चार राज्यों में हो रहे विधान सभा चुनावों में भाजपा के लिए लाभप्रद समझती है।

जीडीपी वृद्धि दरः कितनी सच, कितनी झूठ

31 अगस्त को 2023 को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून 2023 की तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही। मोदी सरकार के कार्यकाल में आंकड़ों का फर्जीवाड़ा जारी है और यह आंकड़ा भी उस फर्जीवाड़े के तरीके से ही तैयार किया गया है। सचमुच यदि जीडीपी वृद्धि दर इतनी ऊंची हो तो उसका रोजगार के क्षेत्र में कुछ असर दिखाई पड़ना चाहिए था। अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बढ़ने से रोजगार और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

भारत की वास्तविकता यह है कि रोजगार बढ़ नहीं रहे हैं, रोजगार का बढ़ना तो दूर रहा जो मौजूदा रोजगार हैं उनमें भी कमी आ रही है। यह तथ्य जीडीपी वृद्धि दर में सरकार के दावों पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनोमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट के अनुसार 2016–17 में देश की कुल श्रम शक्ति 41.24 करोड़ थी जो 2023 में घटकर 40.5 करोड़ रह गई है। यानी इन वर्षों में 77 लाख रोजगार घट गए।

यह उल्लेखनीय है कि अप्रैल से जून 2023 की तिमाही में मैन्युफक्चरिंग क्षेत्र और कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र, दोनों की वृद्धि दर में पिछले वर्षों के मुकाबले कम वृद्धि दर रही। कृषि के बाद ये दोनों क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं। जब तक इन दोनों क्षेत्रों में वृद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती, रोजगार बढ़ने और बेरोजगारी कम होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

वामदलों की रैली की तैयारी के लिए ब्लॉक स्तरीय मीटिंग

गाजीपुर, 4 सितम्बर 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्लॉक कासिमाबाद की बैठक स्थानीय कार्यालय पर संपन्न हुई। इसे सम्बोधित करते हुए भाकपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य अमेरिका सिंह यादव ने कहा कि सरकार की आर्थिक नीतियाँ एकदम से कॉर्पोरेट परस्त हैं। इस नीति में आम आदमी का चेहरा नहीं दिखता। विकास के पूँजीवादी रास्ते ने कमेरी जनता की कमर तोड़ दी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,गरीबी चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक संकट गंभीर हैं। तमाम संवैधानिक परंपराओ का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार तानाशाही के तरफ तेजी से बढ़ रही है। इस सरकार को सत्ता से बाहर करना होगा। प्रदेश किसान सभा के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र यादव ने बोला कि सरकार किसान विरोधी है। प्रांतीय सरकार पूरी तौर पर विफल है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जिला सुखाग्रस्त है बिजली पानी नहीं मिल रहा है। जनता को संगठित करना होगा। जिला सचिव जनार्दन राम ने पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में ब्लॉक मंत्री की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिस पर शमीम अहमद, सुरेंद्र राम, किसान सभा के जिला मंत्री अशोक मिश्र, सुरेंद्र पाल, राजीव सिंह, रामशंकर विश्वकर्मा, शम्भूनाथ यादव,आदि ने सुझाव दिये। बैठक में 11 अक्टूबर को लखनऊ में वामदलों की होने वाली रैली को सफल बनाने, एवं फंड जमा करने और संगठन को सक्रिय करने का निर्णय हुआ। अध्यक्षता सूर्यनाथ कनौजिया ने की।

अडाणी समूह के खिलाफ जांच क्यों नहीं कराती मोदी सरकार

आर.एस. यादव

कुछ समय पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी जिसमें अडाणी समूह द्वारा विदेशों में फर्जी कंपनियों के जरिये हजारों–करोड़ रुपये के शेयरों के लेनदेन, हजारों–करोड़ रुपये भारत से बाहर ले जाने और भारत लाने और इस तिकड़म से करोड़ों रुपये कमाने का जिक्र किया गया था। अब खोजी पत्रकारों के वैश्विक नेटवर्क 'आर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट' (ओसीसीआरपी) ने अडानी कारपोरेट समूह पर गुपचुप तरीके से अपने ही कंपनियों के शेयरों में निवेश और उसी किस्म की अन्य धोखाधड़ी करने के मुद्दे को जगजाहिर किया है। आखिर क्या बात है कि इस तरह के सबूत आने के बाद भी मोदी सरकार अडाणी कारपोरेट समूह के इस काले धंधे के संबंध में जांच कराने को तैयार नहीं?

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नासिर अली शाबान अहली नाम के किसी आदमी ने कई वर्षों तक मारीशस स्थित दो कोषों के माध्यम से अडाणी समूह में करोड़ों डॉलरों शेयरों का लेनदेन किया गया। विनोद अडाणी (जो अडाणी कारपोरेट समूह के प्रमुख गौतम अडाणी का भाई है) के एक ज्ञात कर्मचारी द्वारा संचालित दुबई स्थित एक कंपनी की निगरानी में यह काम किया गया। शेयरों के लेनदेन के इस कारोबार में करोड़ों रुपए के वारे–न्यारे हुए।

कोई नहीं जानता कि यह नासिर अली शाबान अहली नाम का आदमी कौन है। क्या जरूरी नहीं कि इस आदमी का पता लगाया जाए, यह कौन है, इसके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई कि अडाणी समूह के करोड़ों शेयरों का वह लेनदेन और खरीद–फरोख्त करता रहा है?

इसी प्रकार बार चांग–चुंग–लिंग नाम का ताइवान का एक आदमी भी मारीशस स्थित दो कोषों के माध्यम से अडाणी समूह में करोड़ों डॉलरों शेयरों का लेनदेन करता रहा। उसका भी पता नहीं वह कौन है, इतनी बड़ी रकम उसके पास कहां से आई कि अडाणी समूह के करोड़ों शेयरों का वह लेनदेन और खरीद–फरोख्त करता रहा है? क्या इसकी जांच जरूरी नहीं? मोदी सरकार इन मामलों में जांच क्यों नहीं करना चाहती।

खोजी पत्रकारों के वैश्विक नेटवर्क 'आर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट' (ओसीसीआरपी) ने अडानी कारपोरेट समूह पर गुपचुप तरीके से अपने ही कंपनियों के शेयरों में निवेश का आरोप लगाया है।

ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवर्तक परिवार के सहयोगियों द्वारा मारीशस स्थित ऐसे निवेश कोष का इस्तेमाल करके समूह की कंपनियों में गुपचुप तरीके से सैंकड़ों अरब डॉलर का निवेश किया गया, जिनका कोई अता–पता नहीं है। हालांकि, अडाणी समूह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इस निवेश की वजह से 2013 से 2018 के दौरान समूह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल आया।

ओसीसीआरपी ने कहा कि उसे प्राप्त दस्तवेजों में 2013 से 2018 तक समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों का समर्थन करने के लिए प्रवर्तक परिवार के भागीदारों द्वारा प्रबंधित दो मारीशस आधारित कोष में जटिल व अस्पष्ट विवरण सामने आया है। 2013 से 2018 के बीच समूह ने भारत में काफी तेजी से वृद्धि की थी। ओसीसीआरपी ने कहा कि गौतम अडाणी के बड़े भाई विनोद अडाणी के दो करीबी लोग मारीशस आधारित कंपनियों के एकमात्र लाभार्थी हैं। ऐसा लगता है उसके माध्यम से निवेश किया गया।

ओसीसीआरपी द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट 31अगस्त 2023 के फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन में छपी है। रिपोर्ट के अनुसार मारीशस आधारित दो फंडों– एमर्जिंग इंडियन फोकस फंड (ईआईएफएफ) और ई एम रीसर्जेन्ट फंड (ईएमआरएफ)–ने 2013 और 2018 के बीच चार अडाणी कंपनियों में निवेश और बहुत बड़ी मात्रा में शेयरों का लेनदेन किया। इन विदेशी निवेशकों में दो बड़े विदेशी निवेश थे यूएई के नासिर अली शाबान अहली और ताइवान के चांग–चुंग–लिंग।

पैसे को बरमुडा आधारित ग्लोबल ऑपोर्चुनिटीज फंड (जीओएफ) नाम के निवेश फंड के जरिये लाया–ले जाया गया। मार्च 2017 में नासिर अली और चांग–चुंग–लिंग के अडाणी शेयरों का मूल्य लगभग 430 मिलियन डॉलर (उस समय की विनिमय दर के अनुसार, लगभग 2,795 करोड़ रुपए) था। जनवरी 2017 में इन दोनों निवेशकों के पास मिलकर अडाणी एंटरप्राइजिज के 3.4 प्रतिशत, अडाणी पावर के 4 प्रतिशत और अडाणी ट्रांसमिशन के 3.6 प्रतिशत शेयर थे। इसका अर्थ यह भी है कि अडाणी की ये कंपनियां जो मुनाफा कमा रही हैं उनका यह प्रतिशत हिस्सा नासिर अली और चांग–चुंग–लिंग को जा रहा है और मुनाफे का यह हिस्सा कोई हजार–दो हजार रुपए नहीं, हजारों–करोड़ रुपए है।

ओसीसीआरपी की जांच ने यह पर्दाफाश भी किया है कि यूएई आधारित एक्सल इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सर्विसिज लि. नाम की दो रहस्यमयी फर्मो (इन दोनों का स्वामित्व गौतम अडाणी के भाई और अडाणी प्रोमोटर ग्रुप के विनोद अडाणी के पास है) ने जून 2012 से लेकर अगस्त 2014 तक ईआईएफएफ, ईएमआरएफ और जीओएफ से 1.4 मिलियन डॉलर से अधिक रकम प्राप्त की। जांचकर्ताओं ने न केवल बीजक/चालान और लेनदेन के रिकॉर्ड खोज निकाले बल्कि उन्होंने ऐसे आंतरिक ई–मेल भी खोज लिए जिनसे इशारा मिलता है कि ईआईएफएफ, ईएमआरएफ और जीओएफ–ये तीनों फंड एक्सल एन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सर्विसिज लि. की तरफ से, यानी विनोद अडाणी की तरफ से, अडाणी समूह के शेयरों में फंड निवेश कर रहे थे।

अतः यह अब एक प्रथम दृष्टया सबूत है कि ईआईएफएफ, ईएमआरएफ और जीओएफ जैसे संगठन ऐसे फ्रंट थे/ हैं जिनके जरिये विनोद अडाणी ने अडाणी समूह कंपनियों के शेयरों में जबर्दस्त फंड निवेश किए। विनोद अडाणी के अडाणी कंपनियों के बड़ी मात्रा में शेयर हैं और यदि विदेश स्थित व्यक्तियों और नासिर अली शाबान और चांग–चुंग–लिंग जैसे लोगों के जरिये अडाणी की तीन कंपनियों में शेयरहोल्डिंग को (जो वस्तुतः विनोद अडाणी की ही शेयरहोल्डिंग है) जोड़ लिया जाए तो अडाणी एंटरप्राइजिज और अडाणी ट्रांसमिशन में प्रोमोटर ग्रुप की शेयरहोल्डिंग जनवरी 2017 में 78 प्रतिशत से अधिक बैठती है जो सीक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19ए का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके अनुसार प्रमोटर ग्रुप की शेयरहोल्डिंग 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

जनवरी 2023 में एक अमरीकी वित्तीय शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग ने अडाणी समूह पर बही–खातों में धोखाधड़ी तथा शेयरों के भाव में गड़बड़ी के साथ विदेशी इकाईयों के अनुचित उपयोग का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने आरोप लगाया था कि शाबान अहली और चांग–चुंग–लिंग जैसे व्यक्तियों और ईआईएफएफ और ईएमआरएफ जैसे ऑफशोर फंडों (विदेश स्थित कोषों) के जरिये गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी द्वारा कथित टैक्स हेवन देशों में फर्जी कंपनियों का एक विशाल वैश्विक नेटवर्क चलाया जा रहा है जिसके जरिये करोड़ों रुपए का लेनदेन किया जाता है। ओसीसीआरपी ने अब उसी संबंध में और अधिक सबूत पेश किए हैं।

ओसीसीआरपी ने ''शेयर मार्केट में अडाणी ग्रुप कंपनियों की डीलिंग्स'' के संबंध में जनवरी 2014 में डायरेक्ट्रेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) के डायरेक्टर जनरल और सेबी प्रमुख के बीच पत्र व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पर्दाफाश किया है। इस पत्र व्यवहार के एक पत्र में अडाणी पावर प्रोजेक्ट द्वारा कैपिटल इक्विपमेंट इम्पोर्ट्स के ओवर इनवायसिंग (चालान में वास्तविक से अधिक मात्रा) के आरोपों के संबंध में डीआरआई की जांच से मिले सबूतों का एक सीडी भी था जिसमें कहा गया था कि ''इस बात के संकेत हैं कि साईफन किए गए पैसे (अर्थात तिकड़मबाजी से इधर–उधर किए गए पैसे) का एक हिस्सा अडाणी ग्रुप में निवेश और विनिवेश के तौर पर भारत के शेयर बाजारों में गया होगा।''

सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने अभी तक इस तरह के पत्र के पाने और डीआरआई से प्राप्त सबूत के बारे में आज तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया है। इसके बजाय उसने विशेषज्ञ समिति के सामने स्पष्ट तौर पर बताया है कि जून–जुलाई 2020 में शिकायत मिलने के बाद अडाणी ग्रुप की कंपनियों द्वारा नियमों के संभावित उल्लंघन के संबंध में 23 अक्टूबर 2020 को जांच शुरू की गई।

ओसीसीआरपी द्वारा डीआरआई के पत्र के पर्दाफाश से पता चलता है कि सेबी ने या तो तथ्यों को छुपाया और गलत जानकारी दी, जो झूठी गवाही/ शपथ भंग का मामला बनता है; या सेबी के अध्यक्ष ने डीआरआई का पत्र मिलने के बाद उस पर कार्रवाई करने के बजाय अडाणी समूह के खिलाफ चल रही जांच को बंद कर दिया।

एक अत्यंत उल्लेखनीय बात यह है कि जो व्यक्ति उस समय सेबी का अध्यक्ष था वह इस समय अडाणी ग्रुप के टीवी चैनल एनडीटीवी (जिसका अडाणी ग्रुप ने 2022 में अधिग्रहण किया) का ''नॉन–एक्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर–चेयरपर्सन'' है।

यह भी उल्लेखनीय है कि 25 अगस्त 2023 को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने नवीनतम शपथ पत्र में कहा है कि उसमें मार्च 2023 से लेकर अब तक अडाणी–हिंडनबर्ग मामलों में 24 जांचें की हैं। इनमें से 22 जांचें पूरी हो गई जबकि दो के संबंध में अंतरिम रिपोर्टें पेश की गई हैं। यह उल्लेखनीय है कि जो दो जांचें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं उनमें एक मामला सीक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19ए के स्पष्ट उल्लंघन का है।

जांच के अंतर्गत आने वाली अवधि को 1 अप्रैल, 2016 से 30 सितंबर 2020 के बीच की अवधि के मामले में और सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को यह रिपोर्ट दी है कि वह 13 संदेहास्पद विदेश स्थित कंपनियों में ''आर्थिक हित शेयर होल्डर'' को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र टैक्स हेवन देश हैं और वह अभी भी और अधिक विवरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि ओसीसीआरपी ने जिन फंडों–ईआईएफएफ और ईएमआरएफ– का विनोद अडाणी के फ्रंटों के तौर पर उल्लेख किया है वह 13 संदेहास्पद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की सेबी की सूची में भी उनके नाम हैं।

सेबी को जवाब देना होगा कि खोजी पत्रकार जब टैक्स हेवन देशों में स्थित होकर काम करने वाले ईआईएफएफ, ईएमआरएफ और जीओएफ जैसे फंडों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो सेबी जैसी राष्ट्रीय एजेंसी यह जानकारी क्यों नहीं हासिल कर सकी? क्या इससे यह इशारा नहीं मिलता कि सेबी अडाणी समूह की अपराधपूर्ण करतूतों से जानबूझ कर आंख चुरा रहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी–हिंडनबर्ग मामले में दायर अनेक याचिकाओं के संबंध में 2 मार्च 2023 को सेबी को जांच करने का आदेश दिया था। जांच का एक विषय यह था कि क्या सीक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19ए का उल्लंघन हुआ है। जांच के अन्य विषय रिलेटिड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के नॉन डिस्क्लोजर और वर्तमान कानूनों का उल्लंघन करते हुए शेयरों मूल्यों में हेरफेर करने से संबंधित थे। साथ

शेष पेज 14 पर...

केरल ने खारिज की केंद्र की स्मार्ट मीटर योजना

पी श्रीकुमारन

तिरुवनंतपुरमः राज्य में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने राज्य में केन्द्र के प्री–पेडस्मार्ट बिजली मीटर के रोलआउट के लिए कुल व्यय (टोटेक्स) मॉडल को जोरदार ढंग से ''नहीं'' कह दिया है। टोटेक्स मॉडल को लागू न करने और कोई अन्य लागत प्रभावी मॉडल चुनने का निर्णय मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा बुलाई गयी बैठक में लिया गया।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ऐसे संशोधनों के माध्यम से देश की संघीय प्रणाली को खत्म करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया तथा हाल ही में संसद में पारित बहु–राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन का पुरजोर विरोध किया।

आधिकारिक तौर पर कहा गया कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) द्वारा एक वैकल्पिक प्रस्ताव विकसित किया जायेगा। प्रस्ताव के तहतए केएसईबी स्मार्ट मीटर परियोजना के लिए बिलिंग और संबद्ध सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करेगा। परियोजना के लिए आवश्यक संचार प्रणाली के लिए केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (के.फ़ोन) का उपयोग किया जायेगा। केएसईबी का डेटा सेंटर डेटा का स्टॉक करेगा।

पहले चरण में 37 लाख उपभोक्ताओं को प्रीपेडस्मार्ट मीटर से लैस करने का जो फैसला किया गया था उसे राज्य सरकार ने रद्द कर दिया गया है। अब केएसईबी के केवल औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताए जिनकी संख्या तीन लाख से कम है, को ही स्मार्टमीटर से लैस किया जायेगा।

स्मार्ट मीटर रोल–आउट केंद्र–सहायता प्राप्त पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना का एक घटक है। जब 15 जून को परियोजना के लिए निविदा आवेदन खोला गया, तो तीन निजी फर्मों ने भाग लिया, जिनकी सबसे कम बोली 3,475.16 करोड़ रुपये थी। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को प्रति स्मार्ट मीटर 9,500 रुपये का भुगतान करना पड़ता। बोर्ड ने प्रारंभिक चरण में 37 लाख उपभोक्ताओं के लिए परियोजना को लागू करने की योजना बनायी थी।

केएसईबी में वामपंथी और कांग्रेस समर्थित ट्रेड यूनियनों के कड़े विरोध के बाद इस योजना को छोड़ दिया गया। कर्मचारी संगठनों ने इस आधार पर इस योजना का विरोध किया कि इससे निजीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। उनका तर्क था कि बिजली मंत्रालय ने श्रम संगठनों की चिंताओं का समाधान नहीं किया है।

वाम ट्रेड यूनियनों ने भी कहा कि केरल केएसईबी को कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए तुरंत निविदा प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि स्मार्ट मीटर की कीमत 9,500 रुपये के करीब होगी, जबकि बोर्ड द्वारा निर्धारित आधार मूल्य 6,000 रुपये था। राज्य के 1.35 करोड़ उपभोक्ताओं में से लगभग 50 लाख गरीब हैं और स्मार्ट मीटर लगाने में सक्षम नहीं हैं।

करीम ने दावा किया कि राज्य सरकार के सामने विकल्प टोटेक्स मॉडल को छोड़ना है और इसके बजाय सी.डैक द्वारा विकसित तकनीक को अपनाना है, जिसे सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लागू किया जा सकता है। इसके अलावा, ट्रेड यूनियनों के अनुरोध के बाद, वाम दलों ने परियोजना के कार्यान्वयन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहा था कि इससे गरीबों और किसानों पर असहनीय बोझ पड़ेगा।

पिनराई विजयन के बयान में कहा गया है कि कई राज्यों को परियोजना को लागू करने और बिजली वितरण की जिम्मेदारी से हटने और अधिकतम लाभ के लिए इसे निजी कंपनियों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। इससे गरीबों और किसानों पर असहनीय बोझ पड़ेगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन के संबंध में, केरल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 32 के तहत सहयोग राज्य का विषय है। केंद्र सरकार अब नवीनतम संशोधनों के जरिए कानूनी झटके से उबरने और शीर्ष अदालत के फैसले को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है।

केरल के सहकारिता मंत्री वी एन वासवन ने केंद्र सरकार पर ऐसे प्रावधानों को शामिल करने का आरोप लगाया, जिसके तहत राज्य सहकारी रजिस्ट्रार के तहत काम करने वाली वैधानिक समितियों को भी समाप्त किया जा सकता है और बहु–राज्य समितियों में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी सहकारी समिति को शासी निकाय की बैठक के निर्णय और सामान्य निकाय की बैठक में बहुमत से एक बहु–राज्य समिति में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस शर्त को हटा दिया गया है कि बहु–राज्य संघ बनने से पहले राज्य पंजीकरण रद्द कर दिया गया होगा और यह शर्त शामिल की गयी है कि इसे स्वाभाविक रूप से रद्द कर दिया जायेगा।

केरल को यह भी आशंका है कि सोसायटी को अपनी संपत्ति और आय का उपयोग केंद्र सरकार या बड़े कॉर्पोरेट निवेशकों के निर्देश पर करने के लिए मजबूर किया जायेगा। इससे आम लोगों को मिलने वाली सहायता बहुत प्रभावित होगी और सहकारी समितियां उनकी पहुंच से बाहर हो जायेंगी। सबसे निर्दयी कटौती यह है कि संशोधन सहकारी समितियों के स्थानीय आर्थिक संसाधन के रूप में कार्य करने के प्राथमिक उद्देश्य को विफल कर देंगे, जिस पर कोई भी किसी भी समय भरोसा कर सकता है। ये संस्थान नई पीढ़ी के बैंकों जैसी कार्य संस्कृति अपनायेंगे जो केवल मुनाफे के लिए काम करते हैं। यही कारण है कि शीर्ष अदालत ने राज्यों के प्रति अनुकूल रुख अपनाया। जब यह स्पष्ट हो गया कि यह संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन है तो उसने केंद्र सरकार के कदम को रोक दिया।(संवाद)

उप्र खेत मजदूर यूनियन जिला सम्मेलन का संघर्ष का आह्वान

वाराणसी, 29 अगस्त 2023ः उ. प्र. खेत मजदूर यूनियन जिला वाराणसी का चौथा जिला सम्मेलन ग्राम मझवां, विकास खण्ड पिण्डरा, वाराणसी में कंचन बनवासी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन प्रारम्भ होने के पहले यूनियन के झण्डे का झंडोत्तोलन यूनियन की वरिष्ठ सदस्य बसन्ती ने किया। झण्डोत्तोलन के बाद यूनियन के वर्तमान जिलाध्यक्ष श्यामनारायण सिंह के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

यूनियन के प्रान्तीय महासचिव फूलचन्द यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश की हालात बहुत ही खराब हैं वर्तमान भाजपा सरकार संविधान के लिए खतरा बन गयी है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद को समाप्त करने की साजिश कर रही है। महगाई आसमान छू रही है जनता के आवश्यकता की चीजें खरीददारी की पहुंच से बाहर हो गयी हैं, बेरोजगारी का कोई पुरसाहाल नहीं है, कृषि और शिक्षा का आंख मूंदकर निजीकरण किया जा रहा है, सार्वजनिक सम्पत्तियों को कौड़ी के मोल पूजीपतियों को बेचा जा रहा है, किसान, नौजवान, विद्यार्थी, मजदूर, दलित, आदिवासी, व्यापारी, महिलायें सभी सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान हैं, प्रदेश की योगी सरकार का बुलडोजर अलग कहर ढ़ा रहा है दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का सैंकड़ों साल से बने हुए आशियानों को बिना नोटिस के बुलडोज किया जा रहा है लोगों की फरियाद भी इस जालिम सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है, सामन्तों और पुलिस का जुर्म अलग से जारी है कहीं भी कुछ ठीक नहीं है। आज की परिस्थिति में आवश्यकता है कि खेत मजदूर अपने को बड़ी संख्या में लामबंद करें और इन संवेदनहीन सरकारों के खिलाफ निर्मम संघर्ष के बाद तैयार हो जायें, वर्ना अपना वजूद बचाना भी मुस्किल हो जायेगा।

उप्र बीकेएमयू महासचिव फूलचन्द यादव ने खेत मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि खेत मजदूरों ने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर मनरेगा जैसा ऐतिहासिक कानून बनवाया, जिसकी वजह से मजदूरों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन मनरेगा को भी

भारत सरकार असफलताओं का स्मारक बता रही है, लगातार साल दर साल मनरेगा का बजट कम किया जा रहा है, 100 दिन के बजाय केवल 27 दिन काम मिल पा रहा है जबकि यूनियन लगातार मांग कर रही है कि साल में 200 दिन का काम मुहैया कराया जाए, साथ ही 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, लेकिन सरकार खेत मजदूरों की मांगों को अनसुनी कर रही है, आज वर्तमान परिस्थिति में जितने भी मनरेगा जाब कार्डधारक मुल्क में हैं उसके लिए 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित होना चाहिए, लेकिन सरकार मनरेगा को खत्म करके गरीबी की जगह गरीबों को ही खत्म करना चाहती है। आज खेत मजदूरों को अपनी समस्याओं के साथ ही रोजगार, आरक्षण, संविधान और देश को भी बचाने की लड़ाई लड़नी है। उन्होंने खेत मजदूरों को ललकारते हुए कहा कि जातिवाद, साम्प्रदायिकता और क्षेत्रवाद से उपर उठो, जागो और आसन्न खतरे को पहचानो, साथ ही अपने वर्ग दुश्मनों की भी पहचान करो और निर्णायक जंग की रणभेरी बजा दो, देश एक और कुर्बानी मांग रहा है।

सम्मेलन के अन्त में एक 11 सदस्यीय कौंसिल का चुनाव किया गया, जिसके प्रभु बनवासी अध्यक्ष, नन्द लाल व कंचन बनवासी उपाध्यक्ष, शंकर प्रसाद साकेत महामंत्री, कमलेश विश्वकर्मा व विनोद कुमार मंत्री, शनि कुमार बनवासी कोषाध्यक्ष चुने गये। राज्य सम्मेलन के लिए 11 प्रतिनिधियों का भी चुनाव साथ ही किया गया।

सम्मेलन में भाकपा जिला मंत्री जयशंकर सिंह, डा. चुन्नीलाल, भदोही जिले के यूनियन के वरिष्ठ साथी दिनेश चन्द्र यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किये। सम्मेलन का समापन किसान सभा के नेता नन्दा शास्त्री ने किया।

कुशीनगर

इसके अलावा उ. प्र. खेत मजदूर यूनियन जिला कुशीनगर का तीसरा जिला सम्मेलन भी सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन उ. प्र. खेत मजदूर यूनियन के महासचिव फूलचन्द यादव ने किया।

आरएसएस सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए बेताब

अरुण श्रीवास्तव

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जगह बनाने के बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उच्च शिक्षा, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के कामकाज पर नियंत्रण रखने की कोशिशों में है। आरएसएस ने स्कूल स्तर की शिक्षा को नियंत्रित करने और परिभाषित करने के लिए शिक्षा भारती की स्थापना की है। हालांकि, इसने पाठ्यक्रम सामग्री के साथ–साथ छात्रों के आचार –व्यवहार को तैयार करने और उच्च शिक्षा से संबंधित नीतिगत निर्णयों का सुझाव देने के लिए एक अलग विंग बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की है।

आरएसएस और दक्षिणपंथी नेताओं ने जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के खिलाफ एक भयावह अभियान शुरू किया है और इसका मूल कारण यह है कि वे अपने राजनीतिक आधिपत्य के लिए इन संस्थानों को एक प्रमुख खतरा मानते हैं। हाल ही में, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन में उच्च शिक्षा के लिए एक अलग विंग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आरएसएस के प्रति निष्ठावान अध्यापकों का मानना है कि जब तक ये संस्थान वाम ताकतों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आरएसएस शिक्षा और नीति पर अपनी प्रभावी बात और नियंत्रण की आकांक्षा नहीं कर सकता।

संघ ने इन विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण पाने के लिए नरेंद्र मोदी की सेवाओं का इस्तेमाल आरएसएस के सदस्यों या पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं की कुलपतियों और अन्य विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में नियुक्तियों में किया है। संघ को यह स्पष्ट है कि जब तक वह विश्वविद्यालयों से आरएसएस विरोधी शिक्षाविदों और अधिकारियों को नहीं हटाता, तब तक वह इन विश्वविद्यालयों के वामपंथी छात्रों को घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आरएसएस के निर्देश पर मोदी सरकार ने पहले ही हिन्दुत्व का विरोध करने वाले सभी प्रशासकों और शिक्षाविदों को बाहर करने और उन खाली जगहों को बदल कर भरने के लिए नीति बनाई है।

2016 में आरएसएस और मोदी सरकार ने कन्हैया कुमार मामले के मद्देनजर जेएनयू परिसर को साफ कर अपने अनुकूल बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। हालांकि, पिछले पांच वर्षों के दौरान, आरएसएस और मोदी सरकार अन्य विश्वविद्यालयों में अपनी भयावह योजनाओं को आकार देने में सफल रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के लगभग सभी विश्वविद्यालय आरएसएस–भाजपा के नियंत्रण में हैं।

उनकी नवीनतम कोशिश पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बनाने की है। यह एक ज्ञात तथ्य है वामपंथी छात्र आंदोलन के दिनों से लेकर 1970 के शुरुआती दौर की एनएसयूआई तक की छात्र राजनीति ने राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छात्र संघ उन राजनीतिक दलों की रीढ़ रहे हैं जिन्होंने पांचवें दशक के बाद से राज्य पर शासन किया। अब, आरएसएस और भाजपा एबीवीपी को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं ताकि दक्षिणपंथी छात्र और शिक्षण बलों को प्रतिस्थापित किया जा सके और विश्वविद्यालयों के कामकाज पर नियंत्रण हासिल किया जा सके।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डा. सी. वी. आनंद बोस ने 11 राज्य विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति की है और राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने इस कदम को "एकपक्षीय" और कानून का उल्लंघन बताया है। बोस ने 27 विश्वविद्यालयों में वाम और उदारपंथी छात्रों, अध्यापकों, प्रशासकों के प्रतिरोध से पैदा हुए "गतिरोध" का समाधान अंतरिम कुलपतियों की नियुक्तियों से किया है।

पश्चिम बंगाल के शिक्षाविदों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया के कारण बोस ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों का उल्लंघन करते हुए, जाधवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में गणित संकाय सदस्य बुद्धदेब साहू को नियुक्त करने का फैसला किया है। जाधवपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास परिसर के भीतर एक छात्र की दुखद मृत्यु को लेकर चल रहे आंदोलन और विरोध के बीच राज्यपाल बोस ने कुलपति पद पर नियुक्ति की यह प्रक्रिया पूरी की। साहू को आरएसएस के साथ जुड़ाव के लिए जाना जाता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि साहू उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में अयोग्य हैं। साहू आरएसएस के संगठन जातीयताबादी अध्यापक ओ गवेषक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। बोस ने तीन महीने पहले ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सुभरो कमल मुखर्जी को रवींद्र भारती विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति के रूप में नियुक्त किया था। राज्यपाल ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अपने विश्वविद्यालयों की साप्ताहिक गतिविधि रिपोर्ट को राजभवन भेजने के लिए कहा है।

मोदी सरकार के माध्यम से आरएसएस विदेशी वित्त पोषण के प्रवाह की समीक्षा करने के नाम पर अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय कुछ एनजीओ के कामकाज की निगरानी कर रहा है। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नामक एक प्रतिष्ठित संस्था को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, यूजीसी उन विश्वविद्यालयों में सक्रिय रूप से उन विषयों को हटाने में लगा है जिन्हें 'राष्ट्र–विरोधी' और 'देशद्रोही' माना जाता है।

आरएसएस को कोई संदेह नहीं है कि इसकी राजनीति और हिंदुत्व का दर्शन तभी फल–फूल सकता है जब बौद्धिक संपदा पर संघ परिवार के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पूर्ण नियंत्रण हो। आरएसएस अपने मिशन को हासिल करने के लिए मोदी का इस्तेमाल हिंदुत्व समर्थक या भाजपा समर्थक व्यक्तियों को शीर्ष स्तर के संस्थानों का प्रमुख नियुक्त करने के लिए करेगा। जिस तरह से मोदी सरकार ने स्कूलों के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव किया, वह इस चाल का एक स्पष्ट उदाहरण है। शिक्षा अधिकारी इस बात से सहमत हैं कि एनसीईआरटी का नया पाठ्यक्रम इतिहास के बुनियादी सिद्धांतों को तोड़ता है।

आरएसएस अपनी शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों को जिस तेजी से लागू कर रहा है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह पाठ्यक्रम में इन बदलावों को शुरू करने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा है और शिक्षा के मौजूदा तरीके का पूरी तरह हिंदुत्वकरण कर रहा है और बच्चों और युवाओं के बीच हिन्दुत्व विचारधारा की भावना पैदा कर रहा है।

उदारवादी बुलबुले के बाहर आरएसएस नर्सरी से 'वैदिक शिक्षा' को शुरू कर धीरे–धीरे उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने की अपनी नीति को आकार देने में लगा है। धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक ताकतों को आरएसएस की चालों का मुकाबला करने के लिए एक मजबूती के साथ मजबूत तंत्र खड़ा करना होगा।

'आध्यात्मिक स्कूलों' की अपनी श्रृंखला के माध्यम से आरएसएस 'भारत की पारंपरिक मूल्य प्रणाली' को बहाल कर रही है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित स्कूल जैसे कि सरस्वती शिशु मंदिर, शारदा शिशु मंदिर, शारदा शिशु तीर्थ और सरस्वती विद्या मंदिर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, वे 12,754 स्कूल चलाते हैं, जहां 1.5 लाख शिक्षक और 32.92 लाख छात्र उनकी देख रेख में हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. रामकृष्ण राव ने दावा किया है कि "यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है वर्तमान शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह भारतीय मूल्यों, सांस्कृतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संस्थाओं के आधार पर अधिक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और भविष्यवादी बनाने के लिए"।

आरएसएस और दक्षिणपंथी समूह बेताबी से शैक्षणिक संस्थानों में जगह बनाने और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आबादी को आलोचनात्मक और वैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा लेने से वंचित कर उन्हें सांप्रदायिक बनाया जा सके। आरएसएस के शिक्षाविदों का तर्क है कि वैदिक परिणामों और साहित्य की वैज्ञानिक प्रकृति और अंतर्वस्तु है, हालांकि उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए वैज्ञानिक सबूत नहीं दिए हैं।

शिक्षा आरएसएस के लिए प्राथमिक क्षेत्र रहा है, आरएसएस ने नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की है जिसे मोदी लागू कर रहे हैं। मार्च 2017 में दो दिनों के लिए, 51 राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सात सौ से अधिक शिक्षाविदों और कुलपतियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में यह जानने के लिए इकट्ठा हुए कि कैसे 'असली राष्ट्रवादी कहानी' को शैक्षिक जगत में लाया जाए। यह गोपनीय कार्यक्रम ज्ञान संगम, नॉलेज समिट के नाम से हुआ था और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, आरएसएस प्रमुख, मोहन भागवत थे। इस कार्यक्रम में 'शिक्षा प्रणाली पर सांस्कृतिक आक्रमण', 'बुद्धिजीवियों का "उपनिवेशिकारण"' और 'शैक्षणिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान' पर चर्चा हुई थी। नई शिक्षा नीति में जोड़ी गई एक और बड़ी चीज भारतीय ज्ञान प्रणाली है।

यह सही है कि आरएसएस लंबे समय से भारतीय शिक्षा प्रणाली के पूर्ण भगवाकरण की साजिश रच रहा है। आरएसएस शिक्षा का भगवाकरण करने के अपने मिशन को हासिल करने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा था कि आरएसएस उन विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है जो राज्य के कोष से संचालित होते हैं। तथ्य यह है कि मोदी सरकार राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों का इस्तेमाल उन कुलपतियों को नियुक्त करने के लिए कर रही है जिनके आरएसएस के साथ मजबूत संबंध हैं। मुख्यमंत्री विजयन ने फिर भी जोर देकर कहा कि वह केरल को पहले वीसी नियुक्त करने और फिर आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले शिक्षाविदों की नियुक्ति करने की रणनीति के लिए मैदान नहीं बनाएंगे।

सरकार ने सभी 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और दो अन्य संस्थानों को मिलाकर उन्नत भारत अभियान नामक एक परियोजना भी शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य "समावेशी भारत के स्थापत्य निर्माण के लिए ज्ञान संस्थानों की प्रभावान क्षमता द्वारा ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में रूपांतरकारी बदलाव" लाना है। विश्वविद्यालय मात्र इमारतें नहीं हैं जहां पढ़ाई होती है, इमारतें तो किसी भी कोचिंग सेंटर की हो सकती हैं। सर्वप्रथम, विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान है जो विचारों को महत्व देता है और एक ऐसे लोकाचार का निर्माण करता है जहां विचारों का महत्व होता है, इसमें समय लगता है। साफ है कि आरएसएस और दक्षिणपंथी ताकतें इन संस्थानों पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। (आई पी संवाद)

मजदूरों और किसानों का अखिल भारतीय संयुक्त सम्मेलन

घोषणापत्र

24 अगस्त, 2023 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों/ फेडरेशनों/ एसोसिएशनों और संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर आयोजित श्रमिकों और किसानों का यह अखिल भारतीय संयुक्त सम्मेलन, जो कामकाजी लोगों के बड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, देश में 2014 से केंद्र सरकार द्वारा आक्रामक रूप से अपनाई जा रही विनाशकारी और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के कारण हमारे देश के श्रमिकों, किसानों और आम लोगों के सभी वर्गों के सामने उपस्थित चिंताजनक स्थिति का जायजा लेता है। ये नीतियां मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी हैं। ये नीतियां हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों की एकता और राष्ट्र की अखंडता के लिए विनाशकारी साबित हुई हैं। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इन विनाशकारी नीतियों से **'लोगों और उनकी आजीविका को बचाने के लिए'** आने वाले समय में, संयुक्त और समन्वित कार्यक्रम तय करने के लिए किया गया है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू)/ फेडरेशनों/एसोसिएशनों का यह मंच हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों–औपचारिक/संगठित और अनौपचारिक/ असंगठित–के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, और संयुक्त किसान मोर्चा सीमांत, छोटे और मध्यम सहित किसानों के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

किसानों का अनुभव

खेती से लेकर बाजार तक की अंतहीन समस्याओं के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर किसानों को कॉर्पोरेट समर्थक तीन कृषि कानूनों से परेशान किया गया। बड़े कॉर्पोरेट्स ने सरकारी स्वामित्व वाले गोदामों के स्थान पर निजी गोदाम बनाने के लिए जमीन के बड़े हिस्से का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था। यह संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों का दृढ़ संघर्ष ही था, जो 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे, सभी बाधाओं, कठोर मौसम, यहां तक कि कोविड महामारी, उत्पीड़न और सबसे अपमानजनक दुर्व्यवहार का सामना करते हुए (लखीमपुर खीरी की घटना को हम कभी नहीं भूलेंगे) जिसने केंद्र सरकार को अपनी साख बचाने के लिए पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी और बिजली (संशोधन) विधेयक आदि पर किसानों को दिए गए लिखित आश्वासन का भी सम्मान नहीं किया गया है। सरकारी नीतियों के कारण किसानों पर कर्ज बढ़ गया है और किसानों से उनकी आय दोगुनी करने के सारे वायदे धरे के धरे रह गए हैं। पर्याप्त सिंचाई की कमी, गैर–कार्यशील फसल बीमा योजना, सार्वजनिक वितरण योजना को प्रत्यक्ष लाभ योजना से बदलना किसानों की परेशानियों को बढ़ाता है। किसानों द्वारा उत्पादन स्तर को ऊंचा करने के योगदान के बावजूद, कृषि अर्थव्यवस्था लगातार संकट का सामना कर रही है।

श्रमिकों का अनुभव

श्रमिकों को बढ़ती बेरोजगारी, नौकरी छूटने और सभी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। "व्यापार करने में आसानी के लिए" श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के माध्यम से कड़ी मेहनत से हासिल किए गए उनके सभी अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। स्थायी नौकरियाँ तेजी से घट रही हैं आउटसोर्सिंग, विभिन्न प्रारूपों में अनुबंध कार्य, निश्चित अवधि के रोजगार, गिग कार्य आदि के साथ–साथ कुल मिलाकर वास्तविक वेतन स्तर में भारी गिरावट अब सामान्य बात बनती जा रही है। खेतिहर मजदूर जो देश की कृषि आबादी का एक प्रमुख घटक है, सबसे अधिक प्रभावित है और उन्हें पूर्ण गरीबी में धकेल दिया गया है, उन्हें किसी भी सामाजिक सुरक्षा से वंचित होकर बड़ी संख्या में कस्बों और शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक रही है। लेकिन सरकार, 2014 के बाद से, सरकार द्वारा स्वीकृत आईएलओ कन्वेंशनों का भी पालन नहीं कर रही है। प्रथम कन्वेंशन सरकार को प्रतिदिन काम के घंटे 8 तक सीमित करने का आदेश देता है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर इसे बढ़ाकर 12 घंटे कर रही हैं। कन्वेंशन 144 के अनुसार सरकार को वर्ष में कम से कम एक बार त्रिपक्षीय बैठक (सरकारी– नियोक्ता–कर्मचारी) बुलाना चाहिए। मगर अनेक बार मांग किए जाने के बावजूद, इस सरकार ने 2015 से ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई है। सभी लेबर कोड ऐसे परामर्श के बिना पारित किए गए हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है (जून, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में अपनाया गया सर्वसम्मत कन्वेंशन 189), इस सरकार ने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी बंद कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) वापस पाने के लिए और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस, पिछली एनडीए सरकार द्वारा 1999 से 2004 तक लाई गई) को रद्द करने के लिए सरकारी कर्मचारियों–केंद्र और राज्य दोनों–का संघर्ष राष्ट्रव्यापी स्वरुप ले चुका है। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार "पेंशन समितियों" द्वारा इस पर गौर करने का वादा करके बचने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है।

सरकार की नीतियां

निजीकरण इस सरकार की नीतियों के केंद्र में है। जब बीपीसीएल, सीईएल, एयर इंडिया, पवन हंस आदि जैसी दुधारू गायों की बिक्री उस गति से नहीं बढ़ रही थी जैसा वे चाहते थे, सरकार राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) परियोजना लेकर आई, जिसमें लोगों के पैसे से निर्मित विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को बड़े कॉर्पोरेट्स को बिना किसी निवेश के पैसा कमाने के लिए सौंपने का रास्ता शुरू किया गया है। हवाई अड्डे, राजमार्ग, बंदरगाह, रेलवे ट्रैक, स्टेशन सब कुछ बिकाऊ है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। पीएसयू बैंकों का विलय किया जा रहा है और

24 अगस्त, 2023, तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली

निजीकरण की तैयारी की जा रही है। एलआईसी, जीआईसी को निजीकरण का लक्ष्य दिया गया है। यहां तक कि रक्षा उपकरण बनाने वाली 41 आयुध फैक्ट्रियों को भी उनके निजीकरण से पहले 7 निगमों में बदल दिया गया है, जो स्पष्ट रूप से एक राष्ट्र–विरोधी कदम है, जिससे 80000 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। सरकार की नजर रक्षा, रेलवे आदि की विशाल जमीनों पर है। प्रधानमंत्री की विश्व मान्यता के रूप में जी–20 अध्यक्ष पद (जो भारत को उसकी बारी से मिला था) का धूमधाम से प्रदर्शन किया जा रहा है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और आईटीयूसी के विरोध के बावजूद, सरकार एल–20 के प्रमुख के रूप में अपने पसंदीदा ट्रेड यूनियन को नामित करने के लिए आगे बढ़ी। एक तरफ कॉर्पोरेट करों को कम किया जा रहा है और आम लोगों पर जीएसटी का अधिक बोझ और लगभग सभी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के उच्च उपयोगकर्ता शुल्क का बोझ डाला जा रहा है। विपक्ष पार्टियों द्वारा शासित राज्यों को उनके हिस्से का धन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण मनरेगा मजदूरी तथा योजना श्रमिकों के बकाया आदि का भुगतान नहीं हो रहा है। जानबूझकर बैंक डिफॉल्टरों और धोखेबाजों को 'बातचीत और समझौते' के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जबकि जमाकर्ताओं की जमा राशि के लिए केवल 5 लाख रुपये का बीमा किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों के दौरान सार्वजनिक बैंकों द्वारा 14.56 लाख करोड़ रुपये माफ किए गए हैं, लेकिन यह सरकार किसानों का कर्ज माफ करने या उनकी कृषि उपज के लिए सी2+50% एमएसपी दरें प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय कर्ज 153 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

परिणाम

इन नीतियों के परिणामस्वरूप, गरीबी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, मांग सिकुड़ गई है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था लगातार धीमी हो रही है, देश के औद्योगिक आधार का विऔद्योगीकरण (क्मपदकनेजतपंसपेंजपवद) और विनाश, एमएसएमई (डैडम्) का विनाश, आत्मनिर्भरता की हानि तथा लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। बड़े कॉर्पोरेट वर्ग की संपत्ति और आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और मेहनतकश लोगों की बड़ी संख्या दरिद्र हो गई है। भारत में शीर्ष 10% और शीर्ष 1% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 72% और 40.5% हिस्सा है, जबकि निचले 50% (70 करोड़) लोगों की हिस्सेदारी घटकर महज् 3% रह गई है। भारत भूख, गरीबी, बाल देखभाल, महिला सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार आदि सभी सूचकांकों में नीचे गिर रहा है।

हमें चिंता है कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। यहां तक कि सरकारी रिक्तियां भी नहीं भरी जातीं, जो काम सरकार के अधिकार में हैं। कई सार्वजनिक उपक्रमों को बंद किया जा रहा है या निजी पार्टियों को बेचा जा रहा है, जो तुरंत आकर रोजगार कम करना शुरू कर देते हैं, जिससे कई हजार कर्मचारी रोजगार से बाहर हो जाते हैं। संविदा कर्मचारी नौकरी छूटने और छँटनी के प्रमुख शिकार बन गए हैं। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य क्षेत्र के संविदा कर्मचारी (ठेका कर्मचारी) को पक्का करने के वादे के बाद भी अब नौकरी से निकाला जा रहा है। कोविड के बाद, जब जीवन को पटरी पर लाने के लिए नौकरियों की सख्त जरूरत है, ऐसे में कारखानों को अवैध रूप से भी बंद करने की अनुमति दी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है। कोविड के बहाने रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों, खिलाड़ियों को दी जाने वाली रियायतें वापस ले लीं। कृषि गतिविधि, पशुपालन आदि पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो हमारी ग्रामीण आबादी के विशाल बहुमत के भरण–पोषण में बड़ा योगदान देती है, मूल्य अस्थिरता और बिक्री की अनिश्चितता के कारण व्यवस्थित रूप से कुचली जा रही है।

देश के श्रम बाजार में अनौपचारिकता बढ़ती जा रही है। श्रमिक, मुख्य रूप से महिलाएं, दो वक्त की रोटी के लिए स्व–रोजगार और घरेलू व्यापार अपनाती हैं। भारत में कृषि श्रम शक्ति में 33% और स्व–रोजगार किसानों में 48% महिलाएँ शामिल हैं। स्व–रोजगार श्रमिकों और उनके व्यापार को सुविधा, सुरक्षा और विनियमन के लिए कोई कानून/नीति नहीं है। प्रवासी मजदूरों की हालत बिगड़ती जा रही है। डिजिटलीकरण के बड़े दावों के बावजूद उनके लिए कोई पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा नहीं है। बीओसीडब्ल्यू में भारी उपकर (ब्मे) फंड एकत्र होने के बावजूद निर्माण श्रमिक सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निर्माण श्रमिकों के ऑफलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए और उपकर राशि से ईएसआईसी को उन पर लागू किया जाना चाहिए। यहां तक कि ई–श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत लोगों को भी कोई सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। ये सभी वर्ग स्वास्थ्य देखभाल, जीवन और विकलांगता बीमा, वृद्धावस्था लाभ, मातृत्व, बाल देखभाल और शैक्षिक लाभ जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सही हकदार हैं। राज्य सरकारों को श्रमिकों के व्यापार और कौशल में सुधार के लिए कार्य आधारित विशिष्ट योजनाओं का काम सौंपा जाना चाहिए। इससे अनौपचारिक कार्यों का औपचारिकीकरण सुनिश्चित होगा।

संघीय ढांचा और कानून का शासन खतरे में है

केंद्र में सरकार की गतिविधियां हमारे देश के संघीय ढांचे के खिलाफ हैं केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल खुले तौर पर केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जिससे निर्वाचित राज्य सरकारों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, अपनी पार्टी की सरकारें स्थापित करने के लिये निर्वाचित राज्य सरकारें गिराई जाती हैं। केंद्र में एकत्रित जीएसटी (ैज) फंड को राज्य सरकारों के साथ साझा नहीं किया जाता है, जिससे उन्हें अपने उचित बकाया का दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है! केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों (राष्ट्रीय राजधानी सेवा मामले का मामला) को पलटने के लिए अपने बहुमत का इस्तेमाल कर रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का फैसला करने वाली 3 सदस्यीय समिति का पुनर्गठन कर रही है मुख्य न्यायाधीश को हटाकर प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता के साथ सत्तारूढ़ दल के एक मंत्री को शामिल किया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य (म्अपकमदबम) अधिनियम को बदलना, जाहिर तौर पर ब्रिटिश काल के कानूनों को खत्म करना है, लेकिन वास्तव में उन्हें और भी सख्त बनाया

जा रहा है, सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 5 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करना आदि.... सूची लंबी है।

विभाजनकारी साम्प्रदायिक नीतियाँ

लेकिन इससे भी अधिक अशुभ कुछ और भी घटित हो रहा है। यह सरकार और केंद्र में सत्तारूढ़ इस पार्टी के नेतृत्व वाली अन्य राज्य सरकारें, लूट–खसोट के अपने शासन को बनाए रखने के लिए, समाज में जहरीला सांप्रदायिक–विभाजनकारी ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए अति सक्रिय हो गई हैं और मजदूरों, किसानों और आम जनता को उनके ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विभाजित करने और कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए एकजुट संघर्षों को कमजोर करने पर आमादा हैं। यह कॉर्पोरेट स्वामित्व वाली मुख्यधारा मीडिया और सोशल मीडिया ट्रोल सेनाओं के सक्रिय समर्थन से किया जा रहा है। मणिपुर में जारी जातीय (म्जीदपब) संघर्ष के कारण भारी जानमाल की हानि और महिलाओं पर अत्याचार, हरियाणा (नूंह) में हाल की सांप्रदायिक झड़पें और देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की उकसावे की घटनाएं–सभी जगह एक ही विभाजनकारी–ध्रुवीकरण उन्मुख नीति, शासन द्वारा तैयार की गई हैं। समाज के सबसे दलित वर्गों पर लगातार अत्याचार (मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति और यूपी में दो दलित लड़कों पर पेशाब करने की हाल की घटना) और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित महिला पहलवानों पर अत्याचार, जिन्होंने अपने उत्पीड़क, कुश्ती महासंघ के उस समय के अध्यक्ष के खिलाफ आवाज उठाई।

भारत में पिछले साल बिलकिस बानो के बलात्कारियों की समय से पहले रिहाई भी शासक–गुट द्वारा समाज पर रची जा रही उसी विभाजनकारी साजिश की क्रूर अभिव्यक्ति है। और उन सभी का उद्देश्य शोषण के खिलाफ आम लोगों के एकजुट संघर्ष को तोड़ना और बाधित करना है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र की सामूहिक चेतना को झकझोर देने वाली इन सभी घटनाओं पर चुप्पी साधे रहते हैं। लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्ष के सदस्यों को केवल इस सरकार की आलोचना करने के लिए ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसी सरकारी एजेंसियों की मदद से तथा यूएपीए और राजद्रोह अधिनियम आदि जैसे नापाक कानूनों के दुरुपयोग के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आतंक का माहौल बनाना, सभी विरोधों और असहमति को चुप कराना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाना है। शासन की पूरी व्यवस्था जो लोगों के साथ–साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की लूट को बढ़ावा देती है और उसे कायम रखती है, इन कृत्यों से बेनकाब हो गई है।

दृढ़ संकल्पित संयुक्त संघर्ष इस सत्तारूढ़ गुट का सामना कर सकता है संयुक्त किसान मोर्चा के संघर्ष की दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। सरकार को अपने कृषि कानून वापस लेने पड़े। हमारे श्रमिक संगठनों के संयुक्त संघर्षों के माध्यम से, बीपीसीएल, सीईएल, कुछ इस्पात संयंत्रों आदि जैसे कई सार्वजनिक उपक्रमों में निजीकरण प्रक्रिया को रोका जा सका, हालांकि केवल कुछ समय के लिए। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को निजीकरण से बचाना, लोगों का संघर्ष बन गया है। महाराष्ट्र, यूपी, पुडुचेरी, जम्मू–कश्मीर, चंडीगढ़ और हरियाणा में बिजली कर्मचारियों के एकजुट संघर्ष ने सरकारों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने जुझारू एकजुट संघर्षों के माध्यम से, विभिन्न राज्यों में योजना कर्मियों ने अपने पारिश्रमिक में वृद्धि सहित अपनी कई माँगें हासिल कीं। हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में सभी तथाकथित सुधारों को जोर–शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लागत–प्रतिबिंबित टैरिफ व्यवस्था स्थापित करने के लिए बिजली क्षेत्र में क्रॉस सब्सिडी और राज्य की भूमिका की सोच को समाप्त करना है। यह कृषि, एमएसएमई (ढडम्) को बर्बाद कर देगा और बिजली को आम लोगों की पहुंच से बाहर कर देगा।

हमारे लिए क्या करना आवश्यक है

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नवउदारवादी नीतियों के चलते संकट के द्वेष से बचाने के लिए आम लोगों के हाथों में अधिक पैसा देकर, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति बनाते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चालू रखते हैं, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि और विस्तार करने और सार्वभौमिकरण करके, सरकारी वित्त पोषण के साथ सामाजिक सुरक्षा उपाय और ऐसे अन्य उपाय, जैसे कृषि आदानों सहित किसानों को सब्सिडी, राज्य के स्वामित्व वाली मंडियां, उचित एमएसपी (डैच) आदि कृषक समुदाय के संकट को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय हैं। यह कॉर्पोरेट्स, अमीरों और सुपर रिच पर कर बढ़ाकर, संपत्ति कर और उत्तराधिकार कर को बहाल करके किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता भी यही सलाह दे रहे हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि श्रमिकों, किसानों और लोगों को जागरूक किया जाए कि उनका असली दुश्मन, उनके दुखों और राष्ट्र के दुखों का कारण, केन्द्र में ॉर्पोरेट–सांप्रदायिक गठजोड़ द्वारा संचालित राष्ट्र–विरोधी विनाशकारी नीति शासन है। उनसे अपनी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों को बदलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्हें सत्ता से बेदखल करना होगा। हमारे संयुक्त और समन्वित संघर्षों को इतनी ऊंचाई पर विकसित करना है कि केंद्र या राज्य की कोई भी सरकार मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों को लागू करने की हिम्मत न कर सके। मजदूर वर्ग और किसान आंदोलन को बड़े पैमाने पर लोगों के साथ मिलकर, अपनी अगुवाई में इस कार्य को अंजाम देना होगा। यह एक बहुत ही बड़ा कार्य है जिसके लिए हममें से प्रत्येक को अपने सामान्य अनुभव को आम जनता के लिए एक संदेश में बदलने के लिए अथक प्रयास करने की आवश्यकता होगी ताकि सत्ता में बैठे उन लोगों के खिलाफ माहौल बनाया जा सके जो देश और इसके लोगों को अभूतपूर्व संकटों और विनाश की ओर धकेल रहे हैं।

एक ओर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों/फेडरेशनों/एसोसिएशनों के मंच और दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त आंदोलन के संयुक्त और समन्वित संघर्षों के हमारे पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में एक–दूसरे का समर्थन करने के हमारे अनुभव को ध्यान में रखते हुए, श्रमिकों और किसानों का यह संयुक्त सम्मेलन आह्वान करता है कि हमारे देश के मेहनतकश लोगों को संयुक्त और समन्वित संघर्षों को उच्च स्तर तक ले जाना होगा। हमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इस सरकार की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई बढ़ानी होगी। 2023 का पूरा वर्ष अभियानों और जुझारू आंदोलनों का वर्ष होना चाहिए, जिससे सभी स्तरों पर संघर्ष के उच्चतर स्वरूप सामने आएं।

हम निम्नलिखित मांगों के चार्टर पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

मांगों का चार्टर

★ मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण हो, भोजन, दवाओं, कृषि–इनपुट और मशीनरी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाई जाए, पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में काफी कमी की जाए।

★ वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों, खिलाड़ियों को दी जाने वाली रेलवे रियायतें, जो कोविड के बहाने वापस ले ली गई थीं, बहाल की जाएं।

★ खाद्य सुरक्षा की गारंटी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बनाया जाए।

★ सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता के अधिकार की गारंटी हो। नई शिक्षा नीति, 2020 को रद्द करें।

★ सभी के लिए आवास सुनिश्चित करें।

★ वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) कड़ाई से लागू हो वन संरक्षण अधिनियम, 2023 और जैव–विविधता अधिनियम और नियमों में संशोधन वापस लें जो केंद्र सरकार को निवासियों को सूचित किए बिना जंगल की निकासी की अनुमति देते हैं। जोतने वाले को भूमि सुनिश्चित करें।

★ राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन रु. 26000/–प्रतिमाह की जाए।

★ नियमित रूप से भारतीय श्रम सम्मेलन बुलाया जाए।

★ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों व सरकारी विभागों का निजीकरण बंद हो, और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को खत्म करें। खनिजों और धातुओं के खनन पर मौजूदा कानून में संशोधन करें और स्थानीय समुदायों, विशेषकर आदिवासियों और किसानों के उत्थान के लिए कोयला खदानों सहित खदानों से लाभ का 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करें।

★ बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 को वापस लें। कोई प्री–पेड स्मार्ट मीटर नहीं।

★ काम के अधिकार को मौलिक बनाया जाए। स्वीकृत पदों को भरें और बेरोजगारों के लिए नए रोजगार पैदा करें। मनरेगा का विस्तार और कार्यान्वयन (प्रति वर्ष 200 दिन और 600 रुपये प्रति माह मजदूरी)। शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम बनायें।

★ किसानों को बीज, उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी बढ़ाएं, किसानों की उपज के लिए एमएसपी / सी–2+50% की कानूनी गारंटी दें और खरीद की गारंटी दें। किसानों की आत्महत्याओं को हर कीमत पर रोकें।

★ कॉर्पोरेट समर्थक पीएम फसल बीमा योजना को वापस लें और जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, फसल संबंधी बीमारियों आदि के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सभी फसलों के लिए एक व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना स्थापित करें।

★ सभी कृषक परिवारों को कर्ज के जाल से मुक्त करने के लिए व्यापक ऋण माफी योजना की घोषणा करें।

★ केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दिए लिखित आश्वासनों को लागू करें, जिसके आधार पर ऐतिहासिक किसान संघर्ष को निलंबित कर दिया गया था; सभी शहीद किसानों के लिए सिंघु सीमा पर स्मारक, परिवारों को मुआवजा दें और उनके परिवारों का पुनर्वास करें, सभी लंबित मामलों को वापस लें, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर मुकदमा चलाएं।

★ चार श्रम कोड, व निश्चित अवधि के रोजगार कानून को वापस लें और काम पर समानता व सुरक्षा सुनिश्चित करें। श्रम का कैजुएलाइजेशन (ंिेनंसपेंजपवद), व ठेकाकरण बंद करें। असंगठित श्रमिकों की सभी श्रेणियों, जैसे कि घर–आधारित श्रमिक, फेरीवाले, कचरा बीनने वाले, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, योजना श्रमिक, खेतिहर मजदूर, दुकानों/प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले, बोझा ढोने वाले, गिग श्रमिक, नमक बनाने वाले, बीड़ी मजदूर, टॉडी टैपर, रिक्शा ऑटो, टैक्सी आदि चलाने वाले, पूर्व–देशवासी श्रमिक, मछली पकड़ने वाले समुदाय आदि को पंजीकृत किया जाए। पेंशन सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा में पोर्टेबिलिटी गारंटी हो।

★ निर्माण श्रमिकों को कल्याण निधि से योगदान के साथ ईएसआई कवरेज दें, ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं, मातृत्व लाभ, जीवन और विकलांगता बीमा का कवरेज भी दें।

★ घरेलू कामगारों और गृह–आधारित कामगारों पर आईएलओ कन्वेंशन की पुष्टि करें और उचित कानून बनाएं। प्रवासी श्रमिकों पर व्यापक नीति बनाएं, मौजूदा अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1979 को मजबूत करें और उनके सामाजिक सुरक्षा कवर की पोर्टेबिलिटी प्रदान करें।

★ एनपीएस (नई पेंशन स्कीम) खत्म करें, ओपीएस (पुरानी पेंशन स्कीम) बहाल करें और सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें।

★ अत्यधिक अमीरों पर कर लगाएं कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएँ संपत्ति कर और उत्तराधिकार कर पुनः लागू करें।

★ संविधान के मूल मूल्यों – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, विविध संस्कृतियों, भाषाओं, कानून के समक्ष समानता और देश की संघीय संरचना (थ्मकमतंसे जतनबजनतम) आदि पर हमला बंद करें।

राष्ट्रव्यापी कार्रवाई का आह्वान

उपरोक्त मांगों के लिए काम करने के अलावा, हम देश भर के सभी श्रमिकों और किसानों से आने वाले दिनों में निम्नलिखित संयुक्त और समन्वित कार्यों में भाग लेने की पुरजोर अपील ;

1. 3 अक्टूबर 2023 (लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार 2021) को काला दिवस के रूप में मनाते हुए कथित साजिशकर्ता, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने और मुकदमा चलाने की मांग की जाएगी। (कार्रवाई का स्वरूप बाद में घोषित किया जाएगा।)

2. 26 से 28 नवंबर 2023 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में, राजभवनों के सामने दिन–रात महापड़ाव संघर्ष का आयोजन करें। (26 नवंबर 2020 श्रमिकों द्वारा अखिल भारतीय आम हड़ताल का दिन था और किसानों द्वारा संसद तक ऐतिहासिक मार्च का पहला दिन था।)

3. दिसंबर 2023/जनवरी 2024 – देश भर में दृढ़ और व्यापक संयुक्त विरोध प्रदर्शन। (कार्रवाई का स्वरूप बाद में घोषित किया जाएगा)।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व स्वतंत्र फेडरेशनों का मंच एवं संयुक्त किसान मोर्चा

भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला

पेज 3 से जारी...

मात्रा में शेयरों का व्यापार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। मार्च 2017 में एक समय पर, अडानी समूह के स्टॉक में निवेश का मूल्य 430 मिलियन डॉलर था। पैसा एक बेहद जटिल रास्ते से आया जिससे इसका अनुसरण करना अत्यधिक कठिन हो गया। इसे चार कंपनियों और बरमूडा–आधारित निवेश कोष, जिसे ग्लोबल अपॉर्चुनिटिज फंड (जीओएफ) कहा जाता है, के चैनल सक लाया गया था।

इस निवेश में इस्तेमाल की गई चार कंपनियां लिंगो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (बीवीआई) थीं, जिसका स्वामित्व चांग के पास था, अहली के स्वामित्व वाली गल्फ एरिज ट्रेडिंग एफजेडई (यूएई), मध्य पूर्व महासागर व्यापार (मॉरीशस), जिसका अहली लाभकारी स्वामी था, और गल्फ एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (बीवीआई), जिसका अहली नियंत्रक था। पत्रकारों द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, इन निवेशों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मुनाफा हुआ, पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों करोड़ की कमाई हुई क्योंकि ईआईएफएफ और ईएमआरएफ ने बार–बार अडानी स्टॉक को कम कीमत पर खरीदा और इसे ऊंचे दाम पर बेचा। जून 2016 में अपने निवेश के चरम पर, दोनों फंडों के पास अडानी समूह की चार कंपनियों के फ्री–फ्लोटिंग शेयर 8 से लेकर लगभग 14 प्रतिशत तक थेः अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अडानी ट्रांसमिशन।

चांग और अहली के अडानी परिवार से संबंध पिछले कुछ वर्षों में व्यापक रूप से सामने आए हैं। अडानी समूह द्वारा कथित गलत कामों की दो अलग–अलग सरकारी जांचों में इन लोगों को परिवार से जोड़ा गया था। अंततः दोनों मामले खारिज कर दिए गए। पहले मामले में 2007 में वित्त मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा कथित रूप से अवैध हीरा व्यापार योजना की जांच शामिल थी। डीआरआई की एक रिपोर्ट में चांग को योजना में शामिल तीन अडानी कंपनियों के निदेशक के रूप में वर्णित किया गया था, जबकि अहली ने एक ट्रेडिंग फर्म का प्रतिनिधित्व किया था जो इसमें शामिल थी। मामले के हिस्से के रूप में, यह पता चला कि चांग ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी के लो–प्रोफाइल बड़े भाई विनोद अडानी के साथ सिंगापुर का आवासीय पता साझा किया था।

दूसरा मामला एक कथित ओवर–इनवॉइसिंग घोटाला था जो 2014 की एक अलग डीआरआई जांच में सामने आया था। एजेंसी ने दावा किया कि अडानी समूह की कंपनियां आयातित बिजली उत्पादन उपकरणों के लिए अपनी ही विदेशी सहायक कंपनी को 1 बिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करके अवैध रूप से भारत से बाहर पैसा भेज रही थीं। यहां भी, चांग और अहली के नाम सामने आए। अलग–अलग समय में, दोनों व्यक्ति दो कंपनियों के निदेशक थे, जो बाद में विनोद अडानी के स्वामित्व में थीं, जिन्होंने योजना से प्राप्त आय को संभाला, एक संयुक्त अरब अमीरात में और एक मॉरीशस में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, चांग या तो सिंगापुर की एक कंपनी में निदेशक या शेयरधारक थे, जिसे एक अडानी कंपनी के खुलासे में 'संबंधित पार्टी' के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

अडानी के साथ इन पिछले संबंधों के अलावा, इस बात के सबूत हैं कि अडानी स्टॉक में चांग और अहली का व्यापार परिवार के साथ समन्वित था। अडानी समूह के व्यवसाय से परिचित एक सूत्र के अनुसार, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका नाम नहीं लिया जा सकता, ईआईएफएफ और ईएमआरएफ में चांग और अहली के निवेश के प्रभारी फंड मैनेजरों को अडानी कंपनी से निवेश पर सीधे निर्देश प्राप्त हुए। स्रोत ने जिस कंपनी का नाम एक्सेल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड रखा है, वह संयुक्त अरब अमीरात के एक गुप्त अपतटीय क्षेत्र में स्थित है जहां कॉर्पोरेट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, पत्रकारों द्वारा प्राप्त दस्तावेज स्रोत के खाते की पुष्टि करते हैंः

ईआईएफएफ और ईएमआरएफ को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सेल के लिए एक समझौते पर 2011 में खुद विनोद अडानी ने हस्ताक्षर किए थे। हाल ही में 2015 तक, एक्सेल का स्वामित्व असेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के पास था, जिसके बारे में 2016 के एक ईमेल में कहा गया था कि अंततः इसका स्वामित्व विनोद अडानी और उनकी पत्नी के पास था। हालाँकि मॉरीशस, जहां असेंट पंजीकृत है, के वर्तमान कॉर्पोरेट रिकॉर्ड यह नहीं दिखाते हैं कि कंपनी का मालिक कौन है, लेकिन वे बताते हैं कि विनोद अडानी इसके निदेशक मंडल में हैं।

चालान और लेनदेन रिकॉर्ड से पता चलता है कि ईआईएफएफ, ईएमआरएफ और बरमूडा स्थित जीओएफ की प्रबंधन कंपनियों ने जून 2012 और अगस्त 2014 के बीच एक्सेल को 'सलाहकार' शुल्क में 1.4 मिलियन से अधिक का भुगतान किया है। एक आंतरिक ईमेल एक्सचेंज से पता चलता है कि, आगामी ऑडिट के संबंध में, फंड मैनेजर चिंतित थे कि एक्सेल की निवेश सलाह का पालन करने के लिए उनके पास पर्याप्त कागजी कार्रवाई नहीं थी। एक ईमेल में, एक प्रबंधक कई कर्मचारियों को ऐसे रिकॉर्ड तैयार करने का निर्देश देता है जो निवेश के पीछे के तर्क को उचित ठहरा सकें। दूसरे में, एक प्रबंधक एक्सेल से एक रिपोर्ट प्राप्त करने का अनुरोध करता है जिसमें 'फंड ने वास्तव में, निवेश की गई प्रतिभूतियों की संख्या से अधिक में निवेश करने की सिफारिश की है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि निवेश प्रबंधक, ने अपने विवेक का उपयोग किया है निवेश का चयन करने के लिए।

'पैसों की हेराफेरी'

इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अडानी समूह के निवेश के लिए चांग और अहली का पैसा अडानी परिवार से आया था। धन का स्रोत अज्ञात है। लेकिन ओसीसीआरपी द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि विनोद अडानी ने अपने निवेश के लिए मॉरीशस के उसी फंड में से एक का इस्तेमाल किया। रिपोर्टर्स को 2014 में डीआरआई से प्राप्त भारतीय नियामक सेबी का एक पत्र मिला, जिसमें डीआरआई ने कहा कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि जिस कथित ओवर–इनवॉइसिंग योजना की वह जांच कर रहा था, उसका पैसा मॉरीशस भेजा गया था। पत्र में उस समय डीआरआई के महानिदेशक नजीब शाह ने लिखा कि ऐसे संकेत हैं कि निकाले गए पैसे का एक हिस्सा अडानी समूह में निवेश और विनिवेश के रूप में भारत के शेयर बाजारों में पहुंच गया है।

डीआरआई मामले के अनुसार, कथित योजना का पैसा इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा एफजेडई नामक अमीराती कंपनी को भेजा गया था। इसके बाद इस कंपनी ने लगभग 1 बिलियन डॉलर की आय को मॉरीशस स्थित एक होल्डिंग कंपनी को भेज दिया, जिसका स्वामित्व अंततः विनोद अडानी के पास था, जिसका समान नाम इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड था। रिपोर्टर इन फंडों के 100 मिलियन डॉलर से अधिक के आगे के प्रवाह का पता लगाने में सक्षम थे। मॉरीशस कंपनी ने विनोद अडानी की एक अन्य कंपनी, असेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 'एशियाई इक्विटी बाजार में निवेश करने के लिए' पैसा उधार दिया था। इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा होल्डिंग और असेंट दोनों के लाभकारी मालिक के रूप में, विनोद अडानी ने कर्जदाता और उधारकर्ता दोनों के रूप में कर्ज दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अंत में, पैसा जीओएफ में डाल दिया गया, वही मध्यस्थ जो चांग और अहली द्वारा उपयोग किया गया था, और फिर ईआईएफएफ और एशिया विजन फंड, एक अन्य मॉरीशस–आधारित निवेश माध्यम से दोनों में निवेश किया गया।

ओसीसीआरपी कहता है कि सेबी ने 2014 में प्राप्त पत्र के बारे में टिप्पणी के लिए संवाददाताओं के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। इस साल हिंडनबर्ग के आरोपों के मद्देनजर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के अलावा सेबी को जांच करने का निर्देश दिया था।

---

1 सितम्बर– अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी दिवस पर मानव श्रृंखला बनाई

विनाश नहीं विकास चाहिए

अरविन्द पोरवाल

इंदौरः युद्ध की विभीषिका एवं इसके सामाजिक, आर्थिक दुष्परिणामों की और ध्यान आकर्षित करने तथा विश्व में शांति एवं सद्भाव के पक्ष में शांतिप्रिय ताकतों को एकजुट करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 सितम्बर अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन की इंदौर इकाई द्वारा रीगल चौराहे पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने विश्व के तमाम देशों के बढ़ते रक्षा खर्चों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि विनाशक हथियारों के लगातार उत्पादन एवं संग्रहण से सम्पूर्ण मानवजाति के लिए खतरा पैदा हो गया है। अंतर–साम्राज्यवादी शत्रुताएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, सशस्त्र संघर्ष जारी हैं और तीव्र होते जा रहे हैं तथा विश्व शांति के लिए गंभीर खतरे हैं। दूसरी और सरकारों द्वारा समावेशी विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार पैदा करने वाली मदों के बजट एवं अनुदानों में लगातार कटौती की जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि आज सक्षम राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों, खनिज एवं तेल भंडारों पर कब्जा करने एवं अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को लेकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को लगातार बर्बाद करने पर तुले हैं। लीबिया, अफगानिस्तान, सीरिया, फिलिस्तीन, वेनेजुएला इराक, यूक्रेन जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लगातार हिंसा और युद्ध में झोंक कर बर्बाद किया जा रहा है। वक्ताओं ने मांग की है कि दुनिया में हिंसा, आतंक, युद्ध एवं उसके बहाने हथियारों का व्यापार बंद किया जाए एवं सरकार आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समावेशी विकास की जरूरतों पर ध्यान दें। नाटो और सभी सैन्य गठबंधनों को भंग करने, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन और सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता और संप्रभुता के सम्मान की मांग करते हुए वक्ताओं ने अमेरिका, नाटो और यूरोपीय संघ द्वारा विभिन्न देशों के खिलाफ लागू किए गए बहिष्करण, भेदभाव, प्रतिबंध और निषेध की निंदा की, क्योंकि वे कम आमदनी वाले परिवारों, श्रमिकों, गरीब छोटे किसानों और सामान्य तबके के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

कार्यक्रम में रामबाबू अग्रवाल, श्याम सूंदर यादव, रुद्रपाल यादव, अनिल त्रिवेदी, दिलीप वाघेला विनीत तिवारी, राहुल निहोरे, अरविन्द पोरवाल, चुन्नीलाल वाधवानी, रामदेव सायदिवाल, सुनील चंद्रन, विजय दलाल, बी एस सोलंकी, रामस्वरूप मंत्री, हरनाम सिंह, सारिका श्रीवास्तव शफी शेख सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

गुटनिरपेक्षता, वैश्विक शांति और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे एजंडे में शामिल हों

डॉ. अरुण मित्रा

अगले सप्ताह दिल्ली में होने वाली जी–20 बैठक को लेकर काफी उत्साह पैदा किया जा रहा है, विशेष रूप से यह दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही भारत को समूह की अध्यक्षता मिली है, तथा इसी का प्रचार जोर–शोर से किया जा रहा है। परन्तु मामले की सच्चाई यह है कि जी–20 में अध्यक्षता की एक चक्रीय प्रणाली है, जिसके तरह सभी सदस्य देशों को बारी–बारी से आयोजन का अवसर और अध्यक्षता और दी जाती है। दरअसल भारत पिछले साल जी–20 का अध्यक्ष बन सकता था लेकिन इसमें एक साल की देरी हो गयी।

जी–20 के पास चर्चा के लिए कई एजेंडे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक शांति और सभी के लिए स्वास्थ्य है। कई हिस्सों में चल रहे सशस्त्र संघर्षों के कारण आज दुनिया बहुत गंभीर स्थिति में है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष इस समय सबसे गंभीर है। यूएनओ के अनुसार अब तक 3604 नागरिकों सहित 14400 से अधिक लोग मारे गये हैं। 80 लाख से अधिक लोग बाहरी रूप से विस्थापित होकर दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं।

मामला सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं रह गया है। अमेरिका और नाटो की स्पष्ट भागीदारी से चीजें बहुत आगे बढ़ गयी हैं। दोनों पक्षों ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बयान जारी करने के बाद कि वह यूक्रेन को क्लस्टर हथियारों की आपूर्ति करेंगे, रूस ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में उनके पास परमाणु हथियारों का उपयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा। यह बहुत खतरनाक स्थिति है क्योंकि इस समय उस सीमा पर कोई भी परमाणु आदान–प्रदान रूस और यूक्रेन के बीच सीमित नहीं रहेगा। यह रूस और अमेरिका और नाटो के बीच परमाणु आदान–प्रदान होगा। नवीनतम वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इसका मतलब 5 अरब से अधिक लोगों की मृत्यु होगी जो हजारों वर्षों के मानव श्रम के माध्यम से निर्मित आधुनिक सभ्यता का अंत होगा।

आईपीपीएनडब्ल्यू और पर्यावरण समूहों द्वारा किये गये अध्ययन ने पहले ही सुबूतों के साथ दिखाया है कि उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित परमाणु आदान–प्रदान से भी 2 अरब से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन रूस और अमेरिका के बीच आदान–प्रदान कहीं अधिक विनाशकारी होगा।

इसके अलावा अफ्रीका और एशिया के विभिन्न हिस्सों में भी संघर्ष चल रहे हैं। इन आंतरिक झगड़ों को अमीर देशों के विभिन्न आर्थिक हितों के लिए किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है। फिलिस्तीन या सीरिया की स्थिति अत्यधिक मानवाधिकार उल्लंघन के उदाहरण हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जी–20 परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर कड़ा निर्णय ले और छोटे हथियारों के प्रसार पर रोक लगाये।

जी–20 शिखर सम्मेलन का आयोजन

हालाँकि यह असंभावित सा लगता है क्योंकि जी–20 एक समरूप समूह नहीं है। यह बहुराष्ट्रीय निगमों और सैन्य औद्योगिक परिसरों पर हावी स्व–हित वाले देशों का एक समूह है। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नैम) के विपरीत है जिसने प्रभावी कदम उठाये और विभिन्न देशों में निरस्त्रीकरण, विकास और मानवाधिकारों के मुद्दे पर गंभीर चिंताएँ उठायीं। यह सर्वविदित है कि उस समय भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नैम की स्थापना जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और अब्दुल गमाल नासिर की पहल पर की गयी थी। नैम का 7वाँ शिखर सम्मेलन 1983 में दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें 117 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था और कई देशों के 20 पर्यवेक्षक थे।

इसके विपरीत, जी–20 एक छोटा आयोजन है लेकिन बहुत अधिक प्रचार के साथ। ऐसा लगता नहीं है कि जी–20 बैठक परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए एक ठोस घोषणा के साथ सामने आयेगी, जो अब 7 जुलाई 2017 को यूएनओ द्वारा पारित परमाणु हथियारों के निषेध पर बहुपक्षीय संधि (टीपीएनडब्ल्यू) के माध्यम से संभव है।

अंदर एक मजबूत लॉबी है। जी–20 ने यूएनओ में टीपीएनडब्ल्यू का विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों पर जबरदस्त दबाव डाला। ये देश निवारक के रूप में परमाणु हथियारों के सिद्धांत के नायक हैं। इसकी बहुत कम संभावना है कि जी–20 सभी के लिए स्वास्थ्य पर कोई ठोस निर्णय लेकर आयेगा जिसके लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए संसाधनों के समान वितरण की आवश्यकता है।

हमने देखा है कि कैसे फार्मास्युटिकल कंपनियों, विशेष रूप से वैक्सीन उत्पादक कंपनियों ने कोविड महामारी के दौरान तबाही मचायी और छोटे देशों को ब्लैकमेल किया, जिनके पास अपने दम पर वैक्सीन बनाने के लिए न तो तकनीकी जानकारी थी और न ही संसाधन। माना जाता है कि बड़ी फार्मा कंपनियों ने इस अवधि के दौरान भारी मुनाफा कमाया है। सभी के लिए स्वास्थ्य, सस्ती दवा मूल्य निर्धारण और न्यायसंगत स्वास्थ्य देखभाल पर किसी भी बातचीत के लिए, फार्मा कंपनियों को विनियमित करना होगा और उनके मुनाफे को पारदर्शी बनाना होगा।

जी–20 की गतिविधियों और विभिन्न क्षेत्रों में नतीजों पर नजर रखना अच्छा रहेगा। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश कॉर्पोरेट समर्थक विचारधारा और आर्थिक हितों वाले हैं क्या वे हथियार छोड़ने के लिए तैयार होंगे या क्या वे विश्व व्यापार संगठन में प्रभावी बदलाव करने के लिए तैयार होंगे ताकि विकासशील देशों की सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके?

7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारत ने विकासशील देशों को निरस्त्रीकरण, समान विकास, मानवाधिकार, सभी के लिए स्वास्थ्य आदि एक लक्ष्य पर संगठित करने में बड़ी भूमिका निभायी थी। उन्होंने फिलिस्तीनियों के हितों और मानवाधिकारों के अन्य मुद्दों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किये थे। ऐसे फैसलों के लिए स्टेट्समैनशिप की जरूरत होती है। वर्तमान में हमारी राजनीति में उस स्तर के राजनैतिक कौशल का अभाव है। (संवाद)

सलिल चौधरी हिन्दुस्तानी फिल्म संगीत की बहुमुखी प्रतिभा

तीर्थाकर मित्र

भारत ने अभी विदेशी पराधीनता की बेड़ियां हटाई थी, आजादी से भारत के नागरिकों का सपना साकार हुआ। राष्ट्रीयवाद और कई विरोधी आवाजें वातावरण में थीं, इस पृष्ठभूमि में उस समय के कलकत्ता में हाजरा रोड और रुस्सा रोड के चौराहे के पास पेराडाइज कैफे में नौजवानों का एक समूह इकट्ठा हुआ और विभाजित बंगाल के सांस्कृतिक परिवेश को झंकृत करने के लिए अपने नए विचारों को व्यक्त करने लगा।

उस सांस्कृतिक परिवेश में वे मिश्रित शैली वाले व्यक्ति थे जिनका नाम समय के साथ भारत भर में फैला यहां तक कि जब वह बैठक की जगह नहीं रही। उनके विचार और विचारधारा जिस तरह से उनकी साधना में आए उसने अलग–अलग क्षेत्रों में मृणाल सेन, सलिल चौधरी, ऋषिकेश मुखर्जी,तपश सेन, रित्विक घटक और बिजन भट्टाचार्य जैसे दिग्गज दिए।

आजादी अपने साथ विरोध भी लाई और यह विरोध की आवाज सलिल चौधरी की रचनाओं का संगीत बन गई। इस अड्डे में शामिल लोगों में से एक सलिल चौधरी थे जिनकी प्रसिद्धि बंग्ला, हिन्दी, मलयालम गीतों की रचनाओं और उनके संगीत से हुई।

इप्टा के सदस्य सलिल के दो गीत 'बिचारपति तोमार बिचार' और 'धेहू उठहे करा तुतछे' ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिए थे। बंगाल में इप्टा के वरिष्ठ साथियों ने सलिल चौधरी की प्रतिभा को पहचानते हुए उस समय के बढ़ते सांस्कृतिक पुनरुत्थान में उन्हें और अधिक जिम्मेदारियां दीं।

विरोध को व्यक्त करने की सलिल चौधरी की चाह उनके बाद के गीतों में मिलती है। सलिल चौधरी ने रेड आर्मी की मार्चिंग धुन ''पोलयुस्का पोलये'' को ''मौसम बीता जाए'' गाने में एडोप्ट किया।

सलिल चौधरी के दिमाग में जो सुर और धुन बसी हुई थी उनकी कुंजी नवयुवक सलिल की जिन्दगी में मिलती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1925 को एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ, इसी महीने ऋत्विक घटक का जन्म भी हुआ था। सलिल के पिता ज्ञानेन्द्रनाथ चौधरी असम में एक चाय बागान में डॉक्टर थे। उन्होंने अपने पुत्र सलिल के मन में धुन और लय के प्रति अनुराग बोया। सलिल के बड़े भाई निखिल चौधरी ने उनको बांसुरी सिखाई ओर वहां से आगे बढ़कर उन्होंने वायलिन और पियानो सीखा।

इसके बाद सलिल चौधरी ने अपने जीवन में कई धुनें बनाई और उन्होंने उन धुनों को बिलकुल ठीक बजाया। भविष्य की अनिश्चितताओं से सामना करने की चाह उनकी धुनों में मिलती है। सलिल चौधरी के संगीत का रंगपटल बहुत विशाल और विविधतापूर्ण है। लोक संगीत का प्रफुल्ल स्वर प्रसन्नतापूर्वक शास्त्रीय संगीत के साथ मौजूद रहता है। इनके संगीत में स्वरों की असाधारण पेचदारी मिलती है। कंपायमान स्वर खूबसूरती के साथ मध्य ताल में जगह पाते हैं।

विचारों और भावों की आजादी सलिल चौधरी के शुरुआती कामों की पहचान है। सलिल चौधरी ने सुकांत भट्टाचार्य की अवाक पृथ्वी जैसी कविताओं के लिए धुन तैयार की।

जागते रहो, मधुमति, परख, आनंद जैसी कुछ फिल्मों के प्रसिद्ध गीत उन्होंने लिखे और संगीत तैयार किया। बंग्ला और हिन्दी फिल्मी गीतों के उनके कई मुरीद शायद ही केरल के मछुवारे समुदाय पर बनी फिल्म 'दिम्मन'' में उनके द्वारा तैयार संगीत के बारे में जानते होंगे। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा संपादित इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला था। इसमें कोई अचरज नहीं कई मलयाली तो सलिल चौधरी को अपना मानते हैं।

चाय बागान के मजदूरों के गीतों की धुनों की बचपन की उनकी यादें बिना किसी झगड़े के चेम्बर म्युजिक (पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत) से घुलमिल जाती हैं। अपने शुरुआती दिनों में सलिल चौधरी इप्टा के पूर्णकालीन कार्यकर्ता थे। ऋषिकेश मुखर्जी और बिमल राय के कहने पर वे बम्बई पहुंचे और अपने जीवन के नए सफलतापूर्ण चरण की शुरुआत की। कहानीकार, कवि, गीतकार और संगीतकार के अपने सभी अनुभवों को वे बम्बई फिल्म परिवेश में लेकर आए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भारतीय लोक धुनों का पश्चिमी आर्केस्ट्रा और दक्षिणी अमरीकी संगीत के साथ अनूठा फ्यूजन किया।

सलिल चौधरी ने बम्बई यूथ कोयर की स्थापना की। इस यूथ कोयर समूह ने भारत के सभी हिस्सों की लोक और पारंपरिक धुनों के साथ–साथ नागरिक आजादी (सिविल लिबर्टी) और सामाजिक न्याय के आंदोलनों की प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय धुनों को संभाला। बम्बई में काम करने के बाद वे वापिस कलकत्ता आए और संगीत संयोजन के अपने प्रयोगों को जारी रखा और अपने जीवन के अंतिम दिन (5 सितंबर 1995) तक आकांक्षी गायकों को संगीत सिखाते रहे।

असामान्य मूल्य वृद्धि के खिलाफ राज्यभर में असम भाकपा के विरोध प्रदर्शन

कनक गोगोई

गुवाहाटीः असम भाकपा की राज्य परिषद की बैठक 19 और 20 अगस्त को गुवाहाटी में हुई जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं और सभी आवश्यक वस्तुओं की असामान्य मूल्य वृद्धि के खिलाफ राज्यभर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसके जवाब में पार्टी ने असम की सभी जिला इकाइयों ने 28 अगस्त 2023 को विभिन्न प्रकार के विरोध कार्यक्रम का आयोजन किये।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मुनिन महंत ने मैरीगांव शहर में कई पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित जुलूस का नेतृत्व किया और जिला आयुक्त कार्यालय के सामने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। विरोध सभा को संबोधित करते हुए मुनिन महंत ने असामान्य मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में विफलता के लिए मोदी सरकार और राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की।

राज्य कार्यकारिणी के सदस्य पिकुमणी दत्ता और पार्टी के गोलाघाट जिला सचिव होरेन बोरा ने गोलाघाट टाउन में प्रदर्शन कार्यक्रम का नेतृत्व किया और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए गोलाघाट जिले के जिला आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। दोनों नेताओं ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने में विफल रहने के लिए असम के मुख्यमंत्री की तीखी आलोचना की।

राज्य सहायक सचिव अरूप कलिता ने लखीमपुर शहर में प्रदर्शन का नेतृत्व किया और राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि हिमंत बिश्व सरमा असम के एक जनविरोधी मुख्यमंत्री हैं जो केवल अमीर लोगों के लिए काम करते हैं।

शिवसागर भाकपा जिला परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्य सचिव कनक गोगोई और भाकपा जिला सचिव मोनी बुरागोहेन के नेतृत्व में शिवसागर शहर में एक जुलूस और प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने जिला आयुक्त कार्यालय तक मार्च किया और वहां एक विरोध सभा आयोजित की गई। कनक गोगोई ने विरोध कार्यक्रम के महत्व और अपनी मांगों के बारे में समझाया और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में राज्य सरकार की विफलताओं की आलोचना की है। उन्होंने आलोचना करते हुए यह भी कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उसके मंत्री रंजीत कुमार दास असम के लोगों को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। मंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उनके पास नमक को छोड़कर अन्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने की कोई क्षमता नहीं है। मंत्री रंजीत कुमार दास और कुछ अन्य भाजपा मंत्रियों और नेताओं ने भी मूल्य वृद्धि के संबंध में कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। कनक गोगोई ने उनकी अपमानजनक टिप्पणियों का कड़ा विरोध किया और असम के लोगों से 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार और उसके नेताओं को खारिज करने की अपील की। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी जिला आयुक्त के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे। असम के लोगों को सभी आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, भाजपा पार्टी और उसकी सरकार द्वारा बड़े व्यापारियों के साथ अवैध संबंधों को रोकने के लिए, वस्तुओं की कृत्रिम कमी करने वाले बेईमान व्यापारियों को दंडित करने के लिए, राज्य में सभी सिंडिकेट राज को बंद करने के लिए, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने, खराब बिजली के स्मार्ट मीटरों को निरस्त करने आदि की मांगें अपने ज्ञापन में शामिल की।

भाकपा नेताओं रागेन्द्र चौ. दास करीमगंज के जिला सचिव, रंजन चौधरी तिनसुकिया के जिला सचिव, विश्वजीत सैकिया जोरहाट के जिला सचिव, रातुल बोरा नौगांव के जिला सचिव और राज्य सहायक सचिव, जतिन सैकिया डिब्रुगढ़ के जिला सचिव, सुभाष कलिता धेमाजी के जिला सचिव, नलबाड़ी के जिला सचिव तपोन बर्मन, धुबुरी के जिला सचिव महेश राय और गोलपारा जिले के सैलेन दास ने अपने–अपने जिलों में प्रदर्शन कार्यक्रमों का नेतृत्व किया।

जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाकपा व वाम दलों के धरने प्रदर्शन

देहरादूनः भाकपा उत्तराखण्ड ने सरकार की जन विरोधी, मजदूर एवं किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न जिलों में धरने प्रदर्शनों के आयोजन किये। यह आयोजन मुख्य रूप से देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, रूद्रप्रयाग आदि में किये गये। जिन्हें भाकपा के स्थानीय नेताओं ने संबोधित किया। राज्य से प्राप्त समाचार के अनुसार विभिन्न जगहों पर निम्न धरने प्रदर्शन किये गयेः

उत्तरकाशी

जिला मुख्यालय में जिला सचिव भाकपा, महावीर प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है। सरकार की जनविरोधी नीतियोंके खिलाफ तथा किसान एवं मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ और उतराखंड में इस बरसाती मौसम में उत्तराखण्ड के13 जिलों के अन्दर काफी जन–धन की हानि हुई है। यहां तक कि काफी लोगों की जान भी गई है। उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। भाजपा शासित राज्यों में आए दिन सांप्रदायिक माहौल एवं महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है तथा उन्हें निर्वस्त्र कर के घुमाया जा रहा है। यह एक शर्मसार करने वाली घटना है। मोदी सरकार अपने अनुकूल का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा प्रधानमंत्री एवं विपक्षी पार्टी के नेता करेंगे। इसे पलटने के लिए संसद में अध्यादेश लाया गया है। मोदी सरकार की इन्हीं कारगुजारियों का पर्दाफाश करने के लिए भाकपा ने धरने प्रदर्शनों के आयोजन किये हैं।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला सचिव ने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई पर कोई भी कंट्रोल नही है। गैस सिलेंडर दो सौ रूपये कम करने चुनाव में लुभाने और जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन और विकराल होती जा है, गोदी मीड़िया के चैनलो के माध्यम से झूठा प्रचार किया जा रहा है। जनता की आंखो में धूल झोंकी जा रही है। मोदी सरकार द्वारा देश की कुर्बानी का इतिहास बदला जा रहा हूं। उन लोगों का नाम लिखा जा रहा है जिनका देश आजादी में कोई भी योगदान नहीं रहा है। कई धाराओं में संशोधन कर फेरबदल किया जा रहा है। मोदी सरकार सब पर हमला कर रही है। अब मोदी सरकार की उलटी गिनती शुरू हो जायेगी। भट्ट ने जनता को आह्वान किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपाको सबक सिखाने का संकल्प लें। उन्होंने जनता से अपील की है कि भाकपा का प्रतिनिधित्व संसद में बढाए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एकमात्र पार्टी जिसका न कभी झंडा बदला और न कभी निशान बदला और न कभी इस पार्टी का दल बदल का इतिहास रहा है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा 'भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ।' धरने–प्रदर्शन में मुख्य रूप से महावीर प्रसाद भट्ट जिला सचिव, बिशन सिंह चौहान,किशन सिंह पंवार, चतर सिह राणा, विरज मोहन भट्ट, बचना चाहते लाल, पूर्ण सिंह आदि शामिल रहे।

हरिद्वार

5 सितंबर 2023 को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हरिद्वार एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जनपद कमेटी द्वारा वाममोर्चा हरिद्वार के बैनर तले कार्यकर्ता एवं नेता एकत्रित हुए, जनपद हरिद्वार में वर्षा एवं बाढ़ द्वारा गन्ना किसानों के खेतों में गन्ना की फसलों को लगातार वर्षा से काफी नुकसान हुआ है। वहीं धान की फसल बांध टूटने के कारण करीब 15000 किसानों को धान की फसल बांध के पानी द्वारा बर्बाद हो गयी, लोगों के घरों में बरसाती पानी और गंगा का पानी घुसने से काफी नुकसान हुआ है। इस तरह हरिद्वार में इस साल भयंकर बारिश होने से काफी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में भी बाढ़, बिजली गिरने से तर्था बरसात से मकानों, खेतों व सड़कों को नुकसान हुआ है जिसकी वजह से समूचे उत्तराखंड में सभी जगह प्रदर्शन किए। वाममोर्चे के तहत हरिद्वार में सिटी मेजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को उक्त समस्याओं के समाधान हेतु नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। सीपीआई जिला मंत्री मुनरिका यादव और सीपीआई (एम) के जिला सचिव आर. जखमोला द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेड हरिद्वार को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में एम एस वर्मा, एम एस त्यागी, हरीशचन्द्र, सुभाष त्यागी, कालूराम जयपुरिया, भगवान जोशी, साकेश वशिष्ठ, टी. के. वर्मा, भीम सिंह पटेल, जय भगवान, विक्रम सिंह नेगी, सत्य नारायण यादव आदि साथियों ने भाग लिया।

एक अदबी दस्तावेज, जो नई पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है

साल 1936 में लखनऊ में अजीम उपन्यासकार प्रेमचंद की सदारत में एक बड़े जलसे के साथ 'प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना हुई। उसके बाद पूरे मुल्क में इसकी इकाईयों का विस्तार हुआ। बंबई में भी 'अंजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन' की स्थानीय इकाई की हर हफ्ते बैठकें हुआ करती थीं। इकाई के उस वक्त के सेक्रेटरी हमीद अख्तर इन इजलास (सभा) की रूदाद (वृत्तांत) बड़ी पाबंदी के साथ लिखते थे। 'निजाम' में प्रकाशित इन रिपोर्टों की अहमियत को सज्जाद जहीर ने कुछ यूं बयां किया है, ''हमारे जलसे और उनकी बहसें, और रपटें हमारे पूरी तहरीक के लिए एक मिसाली हैसियत इख्तियार करने लगीं। जब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उर्दू के तरक्कीपसंद अदीबों ने अंजुमन की नई शाखाएं खोलीं, तो वे बंबई की तंजीम की तरह जलसे करने और उसकी विस्तृत रिपोर्ट लिखने और उन्हें छपवाने की कोशिशें करने लगे। इस तरह साहित्य सृजन और आलोचना के लिए एक सेहत–मंद माहौल तैयार होने लगा।'' (किताब–'रौशनाई', लेखक–सज्जाद जहीर, पेज–256, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली)

बहरहाल, 1946–47 के तकरीबन डेढ़ बरसों में 'अंजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन' की बंबई शाख ने जो हफ्तावार जलसे किये, उनकी यह रूदाद हमीद अख्तर की किताब 'रूदाद–ए–अंजुमन' में मौजूद है। जिसे साल 2006 में 'तख्लीककार पब्लिशर्स', दिल्ली ने उर्दू में शाए किया था। अब ये अहमतरीन किताब इसी नाम से हिंदी में भी प्रकाशित हो गई है। जिसका लिप्यंतरण, शायर इशरत ग्वालियरी की मदद से लेखक जाहिद खान ने किया है। 'लोकमित्र प्रकाशन' नई दिल्ली से प्रकाशित 'रूदाद–ए–अंजुमन', उस दौर का एक ऐसा अदबी दस्तावेज है, जो नई पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है। किताब में हमीद अख्तर की भूमिका भी शामिल है, जिसमें उन्होंने मुख्तसर में 'रूदाद–ए–अंजुमन' के बारे में अपनी कैफियत बयान की है। 'मुक्ति संघर्ष' के पाठकों के लिए पेश है, लेखक हमीद अख्तर की वह भूमिका.....

अर्ज–ए–हाल

1946–47 में अपने कयाम बंबई के दौरान अंजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन की मुकामी शाख (स्थानीय शाखा) के सचिव के हैसियत से मैं अंजुमन के हफ्तावार जलसों की रूदाद रकम (लिखित) किया करता था। जो डेढ़–दो बरस लगातार बंबई से शाया होने वाले हफ्तावार 'निजाम' में शाए होकर बर्र–ए–सगीर (बंटवारे से पहले का भारत) के कोने–कोने तक पहुंचती रही, बल्कि ये कहना गलत न होगा कि मुल्क के तमाम बड़े–बड़े अदबी मराकिज (बहुत से केन्द्र) में इसका बेचैनी से इंतजार किया जाता था। ये तरक्कीपसंद तहरीक के उरूज का जमाना था। और इस तहरीक से मुताल्लिक तकरीबन सभी बड़े नाम उस वक्त बंबई में मौजूद थे। जिनकी अक्सरियत इन हफ्तावार अदबी जलसों में शरीक होती। इस वजह से उन जलसों की अहमियत और भी बढ़ जाती कि इनकी कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले अमूमन तरक्कीपसंद अदब तख्लीक करने वाले अदीब, शायर और नक्काद होते थे। अदब बराए–अदब (साहित्य, साहित्य के लिए) और अदब बराए–जिंदगी (साहित्य का उद्देश्य जीवन को प्रतिबिंबित करना है) की हैसियत के बावजूद उस जमाने में तरक्कीपसंद और गैर–तरक्कीपसंद अदीबों की तक्सीम इतनी ज्यादा नुमायाँ (प्रकट) नहीं थी। इसलिए मारूफ तरक्कीपसंद अदीबों के अलावा दूसरे बेश्तर अदीब और शायर भी इन जलसों में शरीक होते। मीराजी तो बाकायदा हिस्सा लेने वालों में शामिल थे और उनकी शायरी से इख्तिलाफ (मतभेद) रखने वाले तरक्कीपसंद अदीब भी उनकी तनकीद–आरा (आलोचना के सुझाव) को पूरी तवज्जोह से सुनते और पूरी अहमियत देते थे। हफीज जालंधरी, यगाना चंगेजी, पतरस बुखारी और बहुत से शोअरा (कविगण) और अदीब भी जब कभी बंबई आते, अंजुमन के हफ्तावार जलसों में जरूर शिरकत करते। उस जमाने को गुजरे हुए आधी सदी से ज्यादा अरसा बीत चुका है, मगर इतनी मुद्दत गुजरने के बाद भी पुराने लोग इन हफ्तावार अदबी जलसों की 'निजाम' में शाए होने वाली रिपोर्टों को याद करते हैं। तरक्कीपसंद अदीबों की तंजीम अगरचे ब–वज्ह (उद्देश्य से) इतनी सरगर्म नहीं रही, जितनी 1936 से 1955 तक रही है। ताहम (फिर भी) बर्र–ए–सगीर के

जाहिद खान

दोनों तक्सीमशुदा मुल्कों भारत और पाकिस्तान में गुजिश्ता आधी सदी में जो अदब तख्लीक हुआ है या हो रहा है, इसका गालिबन हिस्सा तरक्कीपसंद निगारशात (लेखन) पर ही मुश्तमिल (आधारित) है। इस दौरान में जदीदियत (आधुनिकता), अलामती (प्रतीकात्मक) अफसाने, इस्लामी अदब वगैरह के बहुत से नारे सुनने

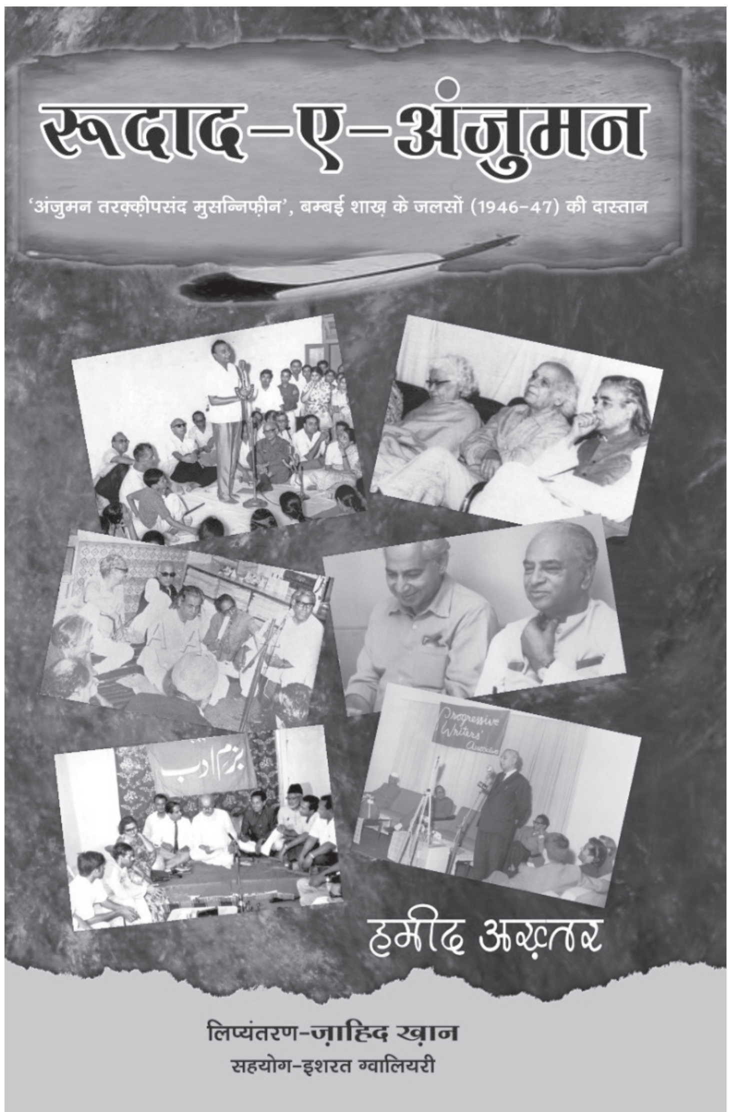

में आए। कुछ लोगों और बाज सामंती इदारों की तरफ से तरक्कीपसंद अदब की तहरीक के मुकाबले में तरह–तरह के बुत खड़े करने की कोशिशें की गईं, मगर आज भी उर्दू अदीबों के साथ–साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दर्जनों इलाकाई जुबानों के हजारों अदीब, जो अदब तख्लीक कर रहे हैं, वो हर लिहाज से तरक्कीपसंद अदब की तारीफ में आता है।

ये सही है कि 1936 के उस जमाने के मुकाबले में जब सज्जाद जहीर, महमुदुल जफर और रशीद जहाँ ने कुछ दूसरे अदीबों और शायरों के साथ मिलकर लखनऊ में 'अंजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन' का पहला जलसा मुनअकिद किया था, अब हालात में बहुत सी तब्दीली आ चुकी हैं। ताहम जो मकासिद उस वक्त इस पहले जलसे में शरीक होने वालों के सामने थे, इनसे अब सर्फ–ए–नजर (देखी–अनदेखी कर देना) करना मुश्किल है। मसलन उन्होंने उस वक्त ये ऐलान किया था कि वो अदब के जरिए समाजी शऊर को फरोग देकर, उसे मुल्क के बदलते हुए मुआशरे की तश्कील (आकार देना) का मु'आवनत (सहायता) बनाएंगे। अगर ब–नजर गाइरा (गहरी नजर से) देखा जाए, तो इस हकीकत से इंकार करना मुश्किल होगा कि इस मकसद के उसूल की आज शायद 1936 के मुकाबले में कहीं ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जिन हकीकतों की मौजूदगी ऊपर लिखे मकासिद के उसूल की मुतकाजी (मांग उपस्थित करने वाला) हुई थी। वो आज भी न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि उनकी शिद्दत में कहीं ज्यादा इजाफा हो चुका है। बहरहाल, अंजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन के इस इब्तिदाई इजलास और अंजुमन के कयाम के बाकायदा ऐलान के बाद पन्द्रह–बीस बरस का ये अरसा उर्दू अदब की तारीख का सुनहरी दौर है। जिसमें तख्लीककारों की एक पूरी खेप ने अदब के जरिए समाजी शऊर के फरोग की जिम्मेदारियों को निभाया। और उर्दू अदब के दौर को फन्नी लिहाज (कलात्मक दृष्टि) से भी बलंद पाए तख्लीकात से मालामाल किया।

उर्दू अफसाने को उसी दौर में जो उरूज हुआ, उसे तरक्कीपसंद तहरीक का रहीन–ए–मिन्नत (आभारी होना) करार दिया जा सकता है। कितने बड़े–बड़े लिखने वाले सामने आए। कृश्न चंदर, मंटो, बेदी, इस्मत, गुलाम अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास और दर्जनों दूसरे लिखने वाले। शायरों में जोश, फैज, अहमद नदीम कासमी, साहिर, फिराक, सरदार जाफरी, कैफी, मजरूह, मजाज, जांनिसार अख्तर, कतील शिफाई, अहमद राही, जहूर नजर, अहमद रियाज, फारिग बुखारी, खातिर गजनवी और बहुत से दूसरे शायर उस दौर की यादगार हैं। ये सिलसिला जारी है और इन नामों मे से कुछ बफज्ल–ए–खुदा (ईश्वर की कृपा से) हमारे दरमियान मौजूद हैं। बाद के आने वालों में इस मर्तबे के लोग शामिल नहीं आए। जिन मर्तबे के लोग तहरीक की मौजूदगी और उससे वाबस्तगी (संबंध) के जमाने में देखने को मिले।

1946–47 का जमाना इस तहरीक के लिए इस लिहाज से भी अहम था कि इस जमाने में मुल्क में आजादी की लहर जारी–ओ–सारी (निरंतर रूप से) थी। और तरक्कीपसंद मुसन्निफीन की तंजीम आजादी की इस जद्दोजहद का एक इंतिहाई सरगर्म हिस्सा थी। चूंकि उस जमाने में तकरीबन सभी नामवर तरक्कीपसंद अदीब और शो'रा बंबई या पूना में मौजूद थे। और बाकायदगी के साथ अंजुमन के हफ्तावार जलसों से शरीक भी होते थे। इसलिए इन जलसों की रूदाद (वृत्तांत) और उसके रिकार्ड को यकीनन तारीखी हैसियत का हामिल (वाहक) करार दिया जा सकता है। इन जलसों में उठाए जाने वाले सवालात जिनका तअल्लुक उस दौर की सियासी, तहजीबी, सकाफती (सांस्कृतिक) और अदबी जिंदगी से था। और उन पर होने वाली बहसों से या अंदाजा किया जा सकता है कि उन लोगों की सोच क्या थी। वो इंसानी तब्दीलियां लाना चाहते थे। मगर बर्र–ए–सगीर की आजादी और तक्सीम–ए–हिंद का अमल जिस तरह तकमील–पजीर (पूरा होने वाला) हुआ और हजारों–लाखों अफराद (व्यक्ति) जिस अफरा–तफरी का शिकार हुए, उसकी वजह से हफ्तावार 'निजाम' में शामिल होने वाला ये कीमती रिकार्ड भी जाए' (नष्ट) हो गया।

अडाणी समूह के खिलाफ जांच क्यों नहीं...

पेज 5 से जारी...

ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह जांचने के लिए कि क्या अडाणी ग्रुप द्वारा कानूनों के उल्लंघन के संबंध में डीलिंग करने में कोई रेगुलेटिरी फेल्योर हुआ है, एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की।

विशेषज्ञ समिति सेबी को पहले ही इस बात के लिए दोषी ठहरा चुकी है कि उसने एफपीआई एंड लिस्टिंग आब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायॅयरमेंट (एलओडीआर) में 2018 में एक ऐसा संशोधन किया जिसके कारण एफपीआई के ''अंतिम लाभप्राप्तकर्ता'' और ''रिलेटिड पार्टियों'' के साथ उनके लेनदेन का पता करना कठिन हो गया है।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद यह समझना मुश्किल नहीं है कि यह संशोधन जानबूझ कर और विनोद अडाणी जैसे लोगों के गैर–कानूनी करोड़ों रुपयों के गोरखधंधे को आसान बनाने और उन्हें कानून के चक्कर से बचाने के लिए किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा अडाणी कारपोरेट घराने द्वारा अरबों रुपए के फर्जी और गैर कानूनी लेनदेन के संबंध में सेबी जिस तरह जांच कर रहा है, उससे नजर यह आता है कि उसकी सारी कोशिश इस दिशा में है कि हिंडनबर्ग द्वारा पर्दाफाश होने के बाद भी अडाणी घराने को कानून के शिकंजे से बचाया जाए।

ओसीसीआरपी नेटवर्क यदि मारीशस स्थित निवेश कोष का इस्तेमाल करके समूह की कंपनियों में गुपचुप तरीके से सैंकड़ों अरब डॉलर के ऐसे निवेश का पता लगा सकता है तो प्रश्न यह उठता है कि सेबी ऐसा करने में विफल क्यों रहा? क्या इसलिए कि मामला अडाणी कारपोरेट घराने से जुड़ा है जिसे भारत के प्रधानमंत्री का बड़ा करीबी समझा जाता है?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ओसीसीआरपी द्वारा अडाणी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर 31 अगस्त 2023 को संवाददाता सम्मेलन में मांग की कि इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन कर गहन जांच कराई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 'जी20' की बैठक से पहले यह मामला सामने आया है और यह देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है। राहुल गांधी ने कहा कि स्पष्ट होना चाहिए कि 'देश से बाहर भेजा गया एक अरब डॉलर' किसका पैसा है? उन्होंने यह सवाल भी किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियां उद्योगपति गौतम अडाणी की जांच और उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही हैं?

उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल जी20 का है। यह दुनिया में भारत की स्थिति को लेकर है। भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे आर्थिक माहौल में पारदर्शिता और व्यापार में समान अवसर हों। इस मामले में भी प्रमुख वैश्विक अखबारों ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 'यह एक सज्जन (गौतम अडाणी) जो भारत के प्रधानमंत्री के करीबी हैं, उन्हें अपनी कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए एक अरब डॉलर स्थानान्तरित करने और उस पैसे का भारतीय संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए उपयोग करने की क्यों अनुमति दी गई है?

उन्हें मुफ्त यात्रा क्यों करने दी जा रही है? राहुल गांधी ने सवाल किया कि ये पैसा किसका है, ये अडाणी जी का पैसा है या किसी और का पैसा है? अगर किसी और का है तो किसका है? उन्होंने दावा किया कि इस पूरे काम में मास्टरमाइंड विनोद अडाणी है, जो गौतम अडाणी के भाई हैं। इसमें दो और लोग नासिर अली शाबान अहली और चीनी नागरिक चांग–चुंग लिंग शामिल हैं।

उन्होंने 2 सितंबर 2023 को रायपुर में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले आर्थिक मामलों के दुनिया के सबसे बड़े अखबार ने लिखा था ' प्रधानमंत्री के करीबी अडाणी ने हिन्दुस्तान से हजारों करोड़ रुपए बाहर भेजे और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर के दाम बढ़ाए।''

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए तथा देश को और बताना चाहिए कि वह अडाणी की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? हिन्दुस्तान से जो हजारों–करोड़ रुपए बाहर गए वह किसका पैसा था, किसी और का था?' गांधी ने कहा, 'मैं आपको साफ कर देता हूं कि हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री अडाणी की कोई जांच नहीं करा सकते क्योंकि जांच का नतीजा निकल गया तो उसका नुकसान अडाणी को नहीं किसी और को होगा।' कांगेस नेता ने आरोप लगाया, 'भाजपा और प्रधानमंत्री हिन्दुस्तान के दो–तीन अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते ही हैं।'

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिकाः भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फैज़ः प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज्बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मृखदूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाषः 011–23523349, 23529823
ईमेलः pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोनः 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास, नई दिल्ली–110 067, फोनः 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोटः आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरणः
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंटः 32074674284, आई.एफ.सी. कोडः SBIN0009371

प्रलेसं प्रगतिशील गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के लिए ....

पेज 16 से जारी...

इस दौर के भारत का गंभीरतम मानवीय दस्तावेज माना गया। इसे तैयार किया कुमार अंबुज और वीरेंद्र यादव ने।

बेहद विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मणिपुर से अधिवेशन में पहुँचे 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के एक लेखक इकेन खूराइजम ने मणिपुर में जारी हिंसा के दौरान सरकार की चुप्पी पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वहाँ आर्थिक और राजनीतिक सवालों को सांप्रदायिकता में बदल दिया गया है। दो महीने तक केंद्र सरकार ने हिंसा को लेकर कुछ नहीं बोला। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे। आज उन्हें राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया है। उन्होने कहा कि हम शांति और न्याय की आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ अपने साथियों के साथ पहुँचे हैं।

इनका हुआ संबोधन

अधिवेशन में इप्टा महासचिव राकेश वेदा, जनवादी लेखक संघ के बालेंदु परसाई, जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार सिंह, धर्मनिरपेक्षता, तर्क तथा वैज्ञानिक चेतना के पैरोकार डॉ. राम पुनियानी, क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना, जनप्रिय कवि नरेश सक्सेना, विभूति नारायण राय, बिहार के राजेंद्र राजन, सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर रवींद्रनाथ राय, पश्चिम बंगाल के अमिताभ चक्रवर्ती, शिवानी, हरियाणा के सुभाष मनसा, स्वर्ण सिंह विर्क, हरविंदर मणिपुर की राजकुमारी निर्मला देवी, छत्तीसगढ़ प्रलेसं के अध्यक्ष नथमल शर्मा, श्रम संगठन एटक के हरिद्वार सिंह, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के निदेशक ईश्वर सिंह दोस्त के अतिरिक्त पंजाब के सुरजीत जज, जसपाल मनखेरा, कुलदीप सिंह दीप, दिल्ली की नव शरण सिंह कौर, फरहत रिजवी, अंजुमन आरा, इप्टा झारखंड के शैलेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश के हिमांशु राय, कुन्दन सिंह परिहार, राजेंद्र गुप्ता, सत्यम, विजेंद्र सोनी, दिनेश भट्ट, आरती, सारिका श्रीवास्तव, केरल के डॉक्टर मोहनदास, उत्तर प्रदेश के वेद प्रकाश, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी, संध्या नवोदिता, डॉक्टर वंदना चौबे, झारखंड के मिथिलेश, राकेश मिश्रा, महादेव टोप्पो ,कर्नाटक के आनंद मेनसे, आंध्र प्रदेश के माधव बुर्रा, प्रोफेसर एन एसवेरा रेड्डी, राजस्थान के प्रेमचंद गांधी, महाराष्ट्र के समाधान इंगले, प्रसेन जीत तेलंग, डॉक्टर सविता लोंढे, डॉक्टर राहुल कौशांबी, गुजरात के ईश्वर सिंह चौहान, तमिलनाडु के एस के गंगा के अलावा अवधेश रानी, युगल रायलु, ज्ञानचंद बागड़ी, अनीश अंकुर, प्रकाश दुबे, सरबजीत सिंह, राजेंद्र दानी, रतन सिंह ढिल्लों, भगवान सिंह चावला ने भी संबोधित किया।

रंग कर्म और साहित्यः

अधिवेशन के विभिन्न सत्रों में विवेचना रंग मंडल के कलाकारों ने अनेक नाट्य प्रस्तुतियाँ दीं। आकर्षक कलात्मक मंच सज्जा का कार्य विनय अंबर ने किया। छत्तीसगढ़ नाचा के कलाकारों ने निसार अली के निर्देशन में परसाई जी की व्यंग्य रचना 'टार्च बेचने वाले' की प्रस्तुति दी। अलंकृति श्रीवास्तव ने 'चिट्ठी जो लिखी नहीं गई' पर एकल नाट्य प्रस्तुति दी। नृत्यांजली कत्थक केन्द्र के कलाकारों ने शैली धोपे के निर्देशन में नागार्जुन एवं पाश की कविताओं पर नृत्य प्रस्तुत किया। जन गीतों का गायन अशोक नगर के हरिओम राजोरिया और उनके साथियों ने तथा मोनोतोषपाल ने बंगाली में किया। आयोजन में सम्मेलन की स्मारिका, उद्‌भावना और बनासजन पत्रिकाएँ तथा अनेक पुस्तकों का विमोचन किया गया। परसाई जी के नाम से निर्मित सभागार में चित्रकारों के पोस्टरों की प्रदर्शनी लगाई गई। गार्गी, सेतु, वाणी और पीपीएच आदि प्रकाशकों ने पुस्तकों के स्टाल लगाए। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान से पेंटिंग उपहार आया लेकिन अधिवेशन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के 10 लेखकों को वीजा न मिलने के कारण वे आयोजन में शिरकत नहीं कर सके। सम्मेलन में देश से जिन लेखकों की अनुपस्थिति याद आती रही वे थे, काशीनाथ सिंह और जयनंदन।

प्रस्ताव जो पारित हुए

अधिवेशन में तीसरे दिन 22 अगस्त 2023 को समापन सत्र से पूर्व अपरान्ह विभिन्न विषयों पर प्रस्ताव रखे गये। इन प्रस्तावों का वाचन विनीत तिवारी, शशिभूषण, शेखर मलिक और शैलेंद्र शैली ने किया। प्रस्तावों का संकलन–संयोजन शशिभूषण ने किया। प्रस्ताव वाचन के बाद सभागार में उपस्थित लेखकों बुद्धिजीवियों कलाकारों ने हाथ उठाकर समर्थन किया तत्पश्चात प्रस्तावों को पारित किया गया। जिन प्रमुख राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रस्ताव पारित हुए वे हैं–मंडला (म. प्र.) स्थित चुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना, मणिपुर में सामुदायिक हिंसा, हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदा, नूँह (हरियाणा) में प्रायोजित सांप्रदायिक हिंसा, रूस–यूक्रेन युद्ध, न्यूज क्लिक के बहाने आजाद मीडिया पर हमला, किसान आंदोलन को धोखा, सरकारी–सांस्थानिक आयोजनों में मनुवाद को बढ़ावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निजीकरण, सांप्रदायिकता एवं हिंदू–राष्ट्र कार्ययोजना।

कार्यकारिणी का गठन

सम्मेलन के तीसरे दिन 22 अगस्त को सांगठनिक सत्र में कार्यकारणी का गठन किया गया।

संरक्षक मंडल में विश्वनाथ त्रिपाठी, पुन्नीलन, काशीनाथ सिंह, डॉ. सैयदा हमीद, गुरबचन भुल्लर, औदेश रानी बावा, डॉ. राजेश्वर सक्सेना को चुना गया।

अध्यक्ष मंडल में राजेंद्र राजन, राजेंद्र शर्मा, वीरेंद्र यादव, कपिल किशन ठाकुर, नथमल शर्मा, शाहीन रिजवी, स्वर्ण सिंह विर्क को जगह मिली।

अध्यक्ष

पी लक्ष्मी नारायण

कार्यकारी अध्यक्ष

विभूति नारायण राय,

और महासचिव सुखदेव सिंह सिरसा को चुना गया।

सचिव मंडल में विनीत तिवारी, डॉक्टर वाल्लिकाउ मोहनदास, अर्जुमंद आरा, अमिताव चक्रवर्ती, मिथिलेश के सिंह, प्रेमचंद गांधी, राकेश वानखेड़े, प्रोफेसर सरबजीत सिंह, टी एस नटराजन, विलपुला नारायणा, प्रोफेसर हरविंदर सिंह, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी के अलावा कार्यकारिणी में इप्टा के कार्यवाहक अध्यक्ष राकेश वेदा एवं महासचिव तनवीर अख्तर को लिया गया। देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधियों को कार्यकारणी में शामिल किया गया। इसी तरह कई वरिष्ठ साथियों को विशेष आमंत्रितों की सूची में रखा गया। मुक्ति संघर्ष में नियमित रूप से लिखने वाले साथी जाहिद खान को भी कार्यकारिणी में लिया गया।

जिला कलेक्टर कार्यालय पर बीकेएमयू का प्रदर्शन

पुदुकोटाई (तमिलनाडु): तमिलनाडु के पुदुकोटाई जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने भारतीय खेत मजदूर यूनियन पुदुकोटाई की जिला ईकाई ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।

बीकेएमयू पुदुकोटाई की मांगों में प्रमुख मांगें थी:

–मनरेगा योजना को शहरी क्षेत्रों में विस्तार करें।

–मनरेगा बजट बढ़ाने और साल में कम से कम 200 दिन काम और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाये।

इन मांगों को लेकर 04 सितंबर 2023 को पुदुकोटाई जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया। इस जोरदार प्रदर्शन की अध्यक्षता आर पालू ने की।

इस प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों में संगठन के महासचिव ए भास्कर, जिला अध्यक्ष ए एल रासु, जिला सचिव ए रेंगराज, कोषाध्यक्ष जेयमाले पिच्छे, भाकपा जिला उपसचिव के आर तर्मराजन और नडराजन प्रमुख थे। उक्त नेताओं ने अपने संबोधन में बीकेएमयू की मांगों के बारे में विस्तार से उपस्थित लोगों को समझाया और वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी संबोधित किया। जिला कलेक्टर को एक मांग पत्र दिया गया। प्रदर्शन में 300 से अधिक खेत मजदूरों ने भाग लिया।

मुक्ति संघर्ष

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, 11 & 12 September 2023

साप्ताहिक 10 – 16 सितंबर, 2023

प्रकाशन तिथि: 8.9.2023

प्रगतिशील लेखक संघ का 18वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न

प्रलेसं प्रगतिशील गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के लिए संकल्पबद्ध

हरनाम सिंह–शशिभूषण

जबलपुर। साम्राज्यवाद और फासिस्ट, साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ लोकतंत्र, समाजवाद लोककल्याणकारी राज्य के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने के आह्वान के साथ अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का तीन दिवसीय 18वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन जबलपुरद्भम.प्र.ऋ के परसाई नगर में 20, 21 और 22 अगस्त को संपन्न हुआ। हरिशंकर परसाई की स्मृति को समर्पित "ठिठुरता गणतंत्र" थीम के साथ उनके शहर जबलपुर में प्रगतिशील लेखक संघ का यह दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन था। इससे 43 साल पहले 1980 में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन के केंद्र में हरिशंकर परसाई की जन्मशती के साथ–साथ हबीब तनवीर, शैलेंद्र, गीता मुखर्जी, रांगेय राघव, मृणालसेन, मायाराम सुरजन आदि की जन्म शताब्दी वर्ष भी थे।

तीन दिन चले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मणिपुर सहित भारत के 20 राज्यों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने की शिरकत। इनमें कितनी ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विभूतियों की मौजूदगी रही। पहले दिन सुबह पोस्टर प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी के उद्घाटन, प्रतिनिधियों के स्वागत सत्र, राष्ट्रीय महासचिव सुखदेव सिंह सिरसा द्वारा प्रतिवेदन वाचन एवं श्र्रांजली सभा से लेकर शाम को विधिवत उद्घाटन सत्र सहित अगले दो दिनों में देर रात तक चलने वाले कुल नौ सत्र हुए। इन सत्रों के विषय थे: गणतंत्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुटता की जरूरत, दमन के खतरों का सामना करना होगा और संविधान के संरक्षण और प्रचार–प्रसार की चुनौतियां, शोषण के खिलाफ सांस्कृतिक दमन, बेहतर समाज के निर्माण में साहित्य की भूमिका, हमारे समय में रोशनी की उम्मीदें, वरिष्ठ लेखकों के साथ युवा प्रतिनिधियों का संवाद सत्र, हमारे समय में लेखकों की भूमिका आदि।

सम्मेलन की शुरुआत 20 अगस्त को सुबह 10 बजे प्रगतिशील लेखक संघ के ध्वजारोहण से हुई। इस ध्वजारोहण में राजेंद्र राजन, विभूतिनारायण राय, सुखदेव सिंह सिरसा और इप्टा के राकेश ने भाग लिया। ध्वजारोहण के बाद पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। उसके बाद सभागार में चित्रकार मुकेश बिजोले, अशोक दुबे, पंकज दीक्षित, रोहित रूसिया, अवधेश बाजपेयी, बालेंद्र परसाई आदि कलाकारों के बनाये पोस्टरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन विभूतिनारायण राय, राजेंद्र राजन और राकेश ने किया। स्वागत सत्र में मंच पर प्रसन्ना, नरेश सक्सेना, राजेंद्र राजन, विभूतिनारायण राय, पी लक्ष्मीनारायण, प्रो. सेवाराम त्रिपाठी, राजेंद्र शर्मा, प्रेमचंद गाँधी, अमिताव चक्रवर्ती, नथमल शर्मा, विनीत तिवारी, सुखदेव सिंह सिरसा उपस्थित रहे। सुखदेव सिंह सिरसा ने प्रलेसं के प्रतिवेदन का वाचन किया और विनीत तिवारी ने मंगलेश डबराल, अली जावेद, प्रभु जोशी आदि दिवंगत लेखकों का स्मरण किया जिन्हें श्रद्धांजलि दी गयी।

शाम साढ़े पाँच बजे जबलपुर शहर में स्थित सभागार में उद्घाटन सत्र आयोजित हुआ। उद्घाटन सत्र से पूर्व एक सदभावना रैली का आयोजन हुआ जिसमें सभी उपस्थित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस रैली में प्रतिनिधियों ने जनगीत गाये, एकजुटता नारे लगाये और संदेशों वाली तख्तियों के साथ सड़क पर शांतिपूर्वक चले। इस दौरान शहरवासियों की उत्सुकता और ठिकना अत्यंत उत्साहवर्धक रहे। रैली में नाचा गम्मत शैली के कलाकारों द्वारा की गयी रुक–रुककर नुक्कण प्रस्तुतियों ने जोश और प्रेरणा का माहौल बनाया। इन प्रस्तुतियों का निर्देशन छत्तीसगढ़ के निसार अली ने किया।

रैली के बाद उद्घाटन सत्र की शुरुआत हरिओम राजोरिया, अशोक नगर (म.प्र.) और साथी द्वारा प्रस्तुत जनगीतों से हुई। इस सत्र में डॉ. सईदा हमीद और प्रसन्ना के वक्तव्य तथा मणिपुर से आये प्रतिनिधिमंडल के हालात वर्णन विशेष रहे। जहाँ डॉ. सईदा हमीद ने अपने मार्मिक संस्मरणात्मक वक्तव्य से हिंदू–मुस्लिम नागरिक एकजुटता का जज्बा पैदा किया वहीं प्रसन्ना ने यह कहकर विचारोत्तेजना पैदा कर दी कि आज के हालात में लेखकों को अब लिखना बंद करके लोगों के बीच जाना चाहिए। अब के हालात में लिखने से कुछ नहीं होगा। लोगों के बीच पहुँचकर ही कुछ बदलाव संभव है। प्रसन्ना के इस वक्तव्य पर हस्तक्षेप करते हुए विनीत तिवारी ने कहा कि लोगों के बीच जाने जितना ही जरूरी लिखना भी है। दोनों काम में परस्पर विरोध नहीं। इन्हें साथ–साथ भी किया जा सकता है। इस सत्र में क्यूबा से आये राजदूत अलेजांद्रो सीमांकास ने सदभावना एवं एकजुटता संदेश दिया। उन्होंने सत्र में अध्यक्षमंडल के लेखकों को चेग्वारा की तस्वीर छपे टी शर्ट भेंट किये। मणिपुर के प्रतिनिधियों ने वहाँ के जमीनी हालात से रुबरू कराया। इस सत्र का मॉडरेशन तरुण गुहा नियोगी ने किया और डॉ. सेवाराम त्रिपाठी ने आभार माना। उद्घाटन सत्र के पश्चात हरिशंकर परसाई के लेखन पर आधारित विवेचना रंगमंडल की नाट्य प्रस्तुति "निठल्ले की डायरी" यादगार रही।

18 वें राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन हरिशंकर परसाई के परिजनों को सम्मानित किया गया। परसाई के नाम पर जबलपुर में चौक, सड़क और मूर्ति स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया। पाकिस्तान से आई हरिशंकर परसाई की पेंटिंग (पोर्ट्रेट) भेंट की गयी। सम्मेलन में राजस्थान के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के साथ ही विभाजनकारी सोच और धार्मिक राष्ट्रवाद को लेकर गंभीर चिंतन सामने आया। अधिवेशन के लगभग सभी सत्रों में वक्ताओं ने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखने वाले जन–संगठनों व देशभर के लेखकों–कलाकारों से एकजुट होकर आम आदमी, किसान, मजदूर, महिला, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, बच्चों के हक के लिए आवाज बुलंद करने का आव्हान किया। सम्मेलन में पी. एस. नटराजन द्वारा प्रलेसं के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुन्नीलन के संदेश का वाचन किया गया। आगामी कार्ययोजना के लिए जबलपुर घोषणा पत्र जारी किया गया। वीरेंद्र यादव द्वारा प्रस्तुत प्रलेसं का जबलपुर घोषणा पत्र

शेष पेज 15 पर...

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन,
15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.